848
11/2/13

खण्ड : 14 संख्या : 11

दशम् बिहार विधान-सभा वादवृत्त

(चर्तुदश सत्र)

(भाग-2 कार्यवाही प्रश्नोत्तर रहित)

बिहार विधान मंडल पुस्तकालय

सत्यमेव जयते

बुधवार, तिथि 13 जुलाई, 1994 ई०

कि संचिका के माध्यम से मुख्यमंत्री जी का आदेश प्राप्त कर नियुक्ति की कार्रवाई की जाय। फिर भी आज तक नियुक्ति नहीं हुई । अब एक साहसी युवक तीन महीना से पटना में भटक रहा है, जिससे मुख्यमंत्री जी के घोषणा पत्र पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। अविश्वास का वातावरण बन रहा है। स्थिति गंभीर है।

अतः हम मांग करते हैं कि इस गंभीर मसले पर विचार किया जाय।

श्री लालू प्रसाद : मैंने घोषणा ही नहीं की है, उससे हाथ मिलाया है, निरीक्षण भी किया है। वह लड़का भी मुझसे मिला था । सरकार की घोषणा अमरवाणी होती है। भले ही उसमें विलम्ब हो, हमने जो घोषणा की थी, उस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं।

अध्यक्ष : अब सभा की बैठक 2.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है।

(अंतराल के बाद)

(इस अवसर पर सभापति श्री राजो सिंह ने आसन ग्रहण किया ।)

वित्तीय-कार्य

वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में सम्मिलित अनुदानों की मांगों पर मतदान :

सभापति :प्रभारी मंत्री, जलापूर्ति और सफाई एवं शहरी विकास आप अपनी मांग प्रस्तुत करें।

श्री गजेन्द्र प्रसाद हिमांशु :सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"जलापूर्ति और सफाई" के संबंध में 31 मार्च, 1995 को समाप्त होनेवाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान में जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिये 2,42,14,43,000 (दो अरब, बयालीस करोड़, चौदह लाख, तैंतालिस हजार) रुपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

सभापति :इस पर जेनरल नेचर का जो कटौती प्रस्ताव है, जिस पर सभी माननीय सदस्य बोल सकते हैं, ये हैं माननीय सदस्या श्रीमती वीणा शाही, माननीय सदस्य श्री सुशील कुमार मोदी एवं माननीय सदस्य श्री खगेन्द्र प्रसाद । जो क्रमांक 65 से 67 तक हैं, वे व्यापक हैं। माननीय सदस्या श्रीमती वीणा शाही, आप अपना कटौती प्रस्ताव मूव करें ।

राज्य सरकार की जलापूर्ति और सफाई कटौती प्रस्ताव एवं बाहरी-विकास नीति पर विचार-विमर्श :

श्रीमती वीणा शाही : मैं प्रस्ताव करती हूं कि :

"इस शीर्षक की मांग 10 रुपये से घटायी जाय ।"

राज्य सरकार की सफाई और जलापूर्ति नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए माननीय सदस्य श्री दिग्विजय सिंह अपना वक्तव्य देंगे ।

श्री दिग्विजय सिंह :सभापति महोदय एवं माननीय विधायकगण, मैं कटौती के प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं आपका ध्यान आकृष्ट करने के पहले एक कहानी सुना देना चाहूंगा । एक गांव में एक ओझा थे और वे बेचारे झाड़-फूंक करके जीवन-यापन किया करते थे। एक दिन जब ओझा जी अपने घर पहुंचे, उनकी पत्नी घर में सोयी हुई थी। गरीबी का आलम था, टिप-टिप वर्षा पड़ रही थी । इसी बीच एक करनी चला आया। ओझाइन सो रही थी। ओझा जी बाहर गये और कहने लगे कि आकाश बांधो, पाताल बांधो, ऊपर बांधो, तभी ओझाइन की नींद खुल गयी और ओझाइन बाहर निकल के ओझा जी पर झपटी और बोली कि साल भर से अपना छप्पर चू रहा है, वो तो बांध ही नहीं सके और कह रहे हो कि आकाश बांधो, पाताल बांधो । मैं कहना चाहता हूं महोदय कि यही स्थिति सरकार की है। हुजूर इनके बजट को देखा जाय, प्रावधान बहुत है, पैसा का डिमान्ड बहुत है, लेकिन अभी तक हो क्या रहा है। मैं स्थिति को स्पष्ट कर देना चाहूंगा। 1972 से 1978 वर्ष में यह निर्णय लिया गया था कि ग्रामों में पेयजल की समस्या को दूर किया जाय। लेकिन जलापूर्ति की जो स्थिति है उस स्थिति को सभापति

महोदय, आपने देखा होगा कि अभी कैसी नारकीय स्थिति बनी हुई हैं इम्पलाइज की हड़ताल चल रही है मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया और इन्होंने यह भी कहा कि हमारे आश्वासन को ये लोग नहीं मानें। लेकिन इसका क्या कारण है। पहले इनके वेतन का 70 प्रतिशत का भुगतान सरकार करती थी और तीस प्रतिशत वे अपने रिसोरसेज से करते थे। फिर हुआ कि उस 70 प्रतिशत में से 40 प्रतिशत सरकार देगी और 30 प्रतिशत ऋण के रूप में देगी, जिसकी कटौती इनके रिसोरसेज से किया जायेगा। लेकिन कटौती करने के लिए जो इनके पास जो रिसोरसेज था, जैसे बस स्टैण्ड, टेम्पो स्टैण्ड, था इस चीज को छीन लिया गया। शिक्षा से सेस रूप से उनको पैसा मिलता था, उसको छीन लिया और सिनेमा हाउस से जो उनको पैसा टैक्स का मिलता था उसको छीन लिया और ऐसी परिस्थिति में उनके बकाये की राशि 1981 में जो निर्णय लिया गया था लोकल बॉडिज...

सभापति : आप क्या बोल रहे हैं, बजट पर बोलिये।

श्री दिग्विजय सिंह : मैं पी० एच० ई० डी० पर बोल रहा हूं। मैं पी० एच० ई० डी० पर ही आ रहा हूं। सभापति महोदय, लोकल बॉडिज की हड़ताल के कारण शहरी एरिया स्लम बन गया है। टंकी की सफाई नहीं हो रही है, पाइप लाइन की सफाई नहीं हो रही है और पी० एच० ई० डी० के इंजीनियर वहां बैठे हुए हैं लेकिन काम नहीं कर पा रहे हैं। नतीजा है कि उस एरिया में कौलरा फैल रहा है और पी० एच० ई० डी० फेलियोर हो रहा है। सभापति महोदय, कुछ खास बात है कि देहातों में जो जलापूर्ति योजना बनायी गयी है उसका डाटा मैं सभा पटल पर प्रस्तुत करूंगा तो आपको आश्चर्य होगा कि किस तरह यह सरकार विफल रही है। 1990-91 में राज्य सरकार द्वारा विभाग को 1803.03 लाख राशि उपलब्ध करायी गयी, जिसमें 715.29 लाख रुपये इन्होंने रेवेन्यू डिपोजिट में जमा कर दिया। उसी तरह 1991-92 में राज्य सरकार ने विभाग को 1930.00 रु० लाख उपलब्ध कराया। नतीजा हुआ कि 1967.16 लाख रुपया सिविल डिपोजिट में जमा कर दिया गया। इस तरह लगातार ये 1993-94 तक पैसा सिविल डिपोजिट में जमा करते जा रहे हैं। और एक भी काम नहीं हो रहा है। सभापति महोदय, यही स्थिति

देहातों में जो चापाकल दिये जा रहे हैं उसकी भी है। इसमें क्या हो रहा है। गड़ाई का पैसा यहां से जा रहा है और वहां डिपार्टमेन्ट को चापाकल गाड़ना है। लेकिन जिसको चापाकल दिया जाता है उसको कहा जाता है कि ढोकर ले जाओ और यह भी कहा जाता है कि गाड़ने का पैसा हम नहीं देंगे । अब एक विधायक का यह काम तो नहीं है कि रोज इन्जीनियर से गाली गुप्ता करे। इसलिए सभापति महोदय, यह विभाग और सरकार दोनों संवेदनशील नहीं है और विभाग और सरकार इस चीज को बहुत छोटा समझती है । समझते हैं कि हमने दे दिया गरीबों का भला हो या नहीं । इस सरकार की ऐसी स्थिति बनी हुई है। सभापति महोदय, शहरी क्षेत्र की स्थिति क्या है। यह निर्णय लिया गया कि जहां 25 हजार की आबादी है वहां पाइप लाइन बिछाया जाय । जहां लोकल बॉडीज नहीं है, वहां भी बनाया जाय। लेकिन देवघर को ले लीजिये, आप वहां अक्सर जाते होंगे । वहां जो पाइप लाइन बनी है, जिसमें 100 के० वी० का ट्रांसफर लगना चाहिए वहां 25 के० वी० का लगाया गया । नतीजा हुआ कि पानी नहीं मिल रहा है। यही हालत सभी जगहों की बनी हुई है। कुछ इन्जीनियर टेक्निकल हैं, उनको सिविल बर्क्स दिया जा रहा है। कुछ ऐसे हैं, जिनको मनमाना जगह पर पोस्टिंग किया जाता है और जितना पैसा वे चाहते हैं पहुंच जाता है और वे जहां चाहते हैं पहुंच जाते हैं और उनको अधिक पैसा दिया जाता है। आखिर कारण क्या है। इसमें क्या खूबी है कि इनको जितना पैसा चाहते हैं मिल जाता है और दूसरी जगह आवंटन कम होता है। सभापति महोदय, सीतामढ़ी जिला के बारे में आपने लिखा है कि जहां बाढ़ और सुखाड़ की स्थिति होती, वहां हम विशेष जलापूर्ति की व्यवस्था करेंगे । लेकिन सीतामढ़ी में क्या हो रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आधा-से-अधिक चापाकल खराब पड़े हुए हैं । ये कहते हैं कि हम रिपेयर के लिए पैसा पंचायतों को देते हैं। लेकिन आप एक पंचायत को 200-300 रुपये देते हैं, क्या इतने कम पैसे से चापाकल गाड़ उखाड़ किया जा सकता है। नतीजा है कि टोटल काम में लूट मची हुई है। मैं किसी एक व्यक्ति को दोषी नहीं मान रहा हूं । इसके लिए पूरा सरकार जिम्मेवार है। इनके कैबिनेट के जो मंत्री हैं वे एक साथ बैठकर निर्णय नहीं लेते हैं अलग रूप से निर्णय लिया जाता है। केन्द्र सरकार जो पैसा देती है वह व्यय नहीं हो पाता है और केन्द्र सरकार का दिया हुआ

पैसा सिविल डिपोजिट में रखा जाता है। ऐसी स्थिति बनी हुई है। मंत्री जी के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं क्योंकि मंत्री अपने मन से काम करने में सक्ष्म नहीं है। सभी मुख्यमंत्री के दबाव में रहते हैं और कोई डिपार्टमेन्ट स्वतंत्र रूप से नहीं चल सकता है। ऐसी स्थिति बनी हुई है कि अगर पैसा दिया जाता है तो सिविल डिपोजिट में पैसा जमा हो जाता है। सभापति महोदय, भंगी मुक्ति आंदोलन चलाने का निर्णय हुआ और उसमें कहा गया कि हम करोड़ों रुपये खर्च करेंगे लेकिन क्या वे बता सकते हैं कि कहां पर इन्होंने भंगी मुक्ति आंदोलन चलाया, इसमें कितना काम किया। इन्होंने कहा था कि सैनिटरी बनाने का काम करेंगे जिसमें 25 हजार रुपया लगेगा लेकिन एक जगह भी यह नहीं बनाया गया। कुछ सार्वजनिक शौचालय सुलभ इंटरनेशनल के द्वारा बनाया गया। देहातों में भंगी मुक्ति के बारे में कोई कार्यक्रम नहीं बनाया गया। यह सरकार संवेदनशील नहीं है। यह पिछड़े, हरिजन का नाम लेती है लेकिन उनके लिए कोई कारगर कदम नहीं उठा पा रही हैं जे० पी० क्रांति के गर्भ से पैदा हुई सरकार है। लेकिन, मुझे तो लगता है कि यह भ्रांति में फंसी हुई सरकार है। इसकी दिशा क्या है यह भी इसको पता नहीं है। सभापति महोदय, ऐसी परिस्थिति बनी हुई है कि पूरा पी० एच० ई० डी० विभाग फेलियोर के कगार पर है। इसलिए इनको एक पैसा भी नहीं मिलना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

व्यवस्था के प्रश्न पर सभापति महोदय का नियमन

श्री अवेधश कुमार सिंह : सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि हमलोग आर ब्लॉक के आवास में रहते हैं हमलोगों के क्वार्टर में एक बूंद भी पानी नहीं मिल रहा है। माननीय मंत्री जब जवाब देंगे उस वक्त इस बात को स्पष्ट करें कि जो विधायक आवास हैं, जहां माननीय विधायक रहते हैं, जो सरकार की नाक के नीचे है, उस जगह जब सरकार पानी नहीं दे सकती है, तो देहातों में कहां तक पानी दे सकते हैं।

सभापति : आवास विभाग के मंत्री मिश्रा जी हैं सारी व्यवस्था आवास विभाग को करनी है। पानी की व्यवस्था आवास विभाग करेगी, बिजली की व्यवस्था करेगी । एक सप्ताह से ये इस बात को उठा रहे हैं।

श्री राम विलास मिश्र :पानी की व्यवस्था पी० एच० ई० डी० करेगा।

श्री गजेन्द्र प्रसाद हिमांशु : सभापति महोदय, पी० एच० ई० डी० का है लेकिन शहरी जलापूर्ति नगर विकास विभाग के अन्दर आता है।

(व्यवधान)

सभापति : यह आपका डिपार्टमेंट है, क्या डिस्कसन किया जाए, बतलाइये आप ही ।

श्री जयप्रकाश नारायण यादव :बोरिंग कराने का काम आप ही का है।

(व्यवधान)

सभापति : मंत्री की ज्वायंट रेस्पोंसिबिलीटी होती है। कोई तो बोलिये कि पानी दीजियेगा या नहीं ?

श्री गजेन्द्र प्रसाद हिमांशु : माननीय विधायकों के लिए जो आवास है। वहां पर एक नया ट्यूबवेल किया गया है और उस नये ट्यूबवेल को पाइप लाइन से जोड़ा जाएगा । जब यह नया ट्यूबवेल काम करना शुरू करेगा तो पानी की दिक्कत नहीं होगी ।

सभापति : तो पानी पियेगा कैसे ? आप पाइप जोड़ने की बात कह रहे हैं। विधान सभा सत्र जिस दिन से चला है उसी दिन से यह बात उठ रही है। बिना पानी के भी कोई रहेगा ? कैसे पानी पियेगा, कैसे स्नान करेगा, कैसे हाउस में आयेगा ?

श्री नवल किशोर भारती : मैं तीन वर्ष से वहां रह रहा हूं लेकिन वहां भी पानी की बहुत दिक्कत है।।

सभापति : सुनिये ।

श्री रवीन्द्र चरण यादव :सभापति महोदय, माननीय मंत्री पी० एच० ई० डी० के पदाधिकारियों, नगर विकास के पदाधिकारियों और वाटर बोर्ड के पदाधिकारियों से टेलीफोन पर बात करके अपने भाषण

के क्रम में बतलायेंगे कि माननीय सदस्यों के लिए पानी की सुव्यवस्थित व्यवस्था हम करेंगे ।

सभापति : यह व्यवहारिक बात आपने नहीं कही। आप एक माननीय सदस्य हैं और ट्रेजरी बेंच में आकर आप भाषण दे दिये । यह नियमानुकूल नहीं है, उचित नहीं है। मंत्री सामने बैठे हुए हैं। दोनों कैबिनेट मिनिस्टर आगे बैठे हुए हैं। आप बतलाइये कि कितने समय में, आज पांच बजे के पहले, आप अपने विभाग से परामर्श करें, या जिनसे जरूरत हो, परामर्श करके आप एनाउन्स करेंगे, अपने उत्तर में कहें या नहीं ? यह जवाब सुनने के लिए तैयार नहीं हैं कि, आप पाइप जोड़ियेगा तब पानी मिले, यह ठीक बात नहीं है। बतलाइये कि क्या व्यवस्था कीजियेगा ? चापाकल लगवाइये या टंकी से पानी पहुंचवाइये । मेला लगता है कि राजगीर में तो टेम्पोररी ऐरेंजमेंट करते हैं या नहीं ?

श्री गजेन्द्र प्रसाद हिमांशु : सभापति महोदय, जिस बिन्दु को आपने उठाया है यह बहुत गम्भीर मामला है। इस पर बहस भी हुई है कौन्सिल में भी और विधान-सभा में भी। सभापति महोदय, विधायक आवासों में पानी की समस्या बराबर बनी रहती है, इसका कारण है कि आस-पास में जो होटल बने हुए हैं वे पानी होटल में ले जाते हैं। कभी-कभी पाइप लाइन की गड़बड़ी के चलते भी ऐसा हो रहा है।

सभापति : कोई रास्ता निकालिये.।

श्री गजेन्द्र प्रसाद हिमांशु : एक योजना बनी है । इस योजना पर कार्य भी हो रहा है। हमलोग प्रयास में लगे हुए हैं कि जल्द-से-जल्दी पानी की आपूर्ति हो सके। कभी-कभी पानी का अभाव मोटर जल जाने के कारण भी हो जाता है या छोटी-मोटी मैकेनिकल गड़बड़ी के चलते भी हो जाता है ।

सभापति : आप टेम्पोररी व्यवस्था क्या कर सकते हैं ?

श्री गजेन्द्र प्रसाद हिमांशु :इसके लिए सरकार व्यवस्था करेगी।

(व्यवधान)

सभापति : इन्होंने कहा कि व्यवस्था करेंगे। चापाकल भी हो सकता है, टंकी से पानी भी पहुंचाया जा सकता है। आप टंकी से पानी पहुंचाइये।

(व्यवधान)

इंतजाम ये कर रहे हैं दो दिन-एक दिन लगेगा। उसके लिए या तो चापाकल गड़वाइये या टंकी से पानी पहुंचवाइये और जल्द-से-ज़ल्द जो आपकी योजना है उसको पूरा करके मेम्बर को पानी दीजिए।

श्री राधाकांत यादव : सभापति महोदय, ये होटल की बात करते हैं।

सभापति :मंत्री जी ने तो आश्वास दिया है कि टेम्पोररी व्यवस्था करेंगे तो बात अब खत्म हो गई।

वित्तीय कार्य :वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में सम्मिलित अनुदानों की मांगों पर मतदान : "जलापूर्ति और सफाई"

श्री राज कुमार महासेठ : सभापित महोदय, अभी लोक स्वास्थ्य विभाग और नगर विकास विभाग की मांग पर कटौती प्रस्ताव के विरोध में और सरकार की जो मांग है उसके पक्ष में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं सभापति महोदय, आज की जो मांग है उसकी अहमियत को हमको समझना चाहिए और पार्टी लाइन बैरियर से ऊपर उठकर हमको सोचना होगा। जब तक उस सिरियसनेस के साथ हम नहीं सोचेंगे, तो सही माने में जो समस्या है पेयजल की, जो शहरी क्षेत्रों की समस्या है, उन समस्याओं का निदान हम नहीं कर सकते हैं सभापति महोदय, सभी लोग यह कह रहे हैं कि हमारी मांग है कि पेयजल की समुचित व्यवस्था की जाए। सभापति महोदय, जो आंकड़े दिये गये हैं उस ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। शहरी जलापूर्ति पर 1990-91 में जो प्रावधान किया गया था वह 13 करोड़ 45 लाख 80 हजार रुपया था और 1994-95 में जो प्रावधान किया गया है, जो अभी की सरकार ने किया है वह 34 करोड़ एक लाख 37 हजार रुपये का है। ग्रामिण जलापूर्ति पर 90-91 में जो प्रावधान था और 94-95 में जो प्रावधान किया गया है, वह पहले

से दूना प्रावधान किया गया है। स्थानीय निकाय आदि आंकड़े की ओर मैं नहीं लें जाना चाहता हूं लेकिन वास्तव में जो भी राशि हमने आंवटित की है और सदन में जो मांग की है वह नगण्य है, जो हमारी समस्यायें हैं उनको देखते हुए। लेकिन सभापति महोदय, माननीय सदस्य जो उधर के बेंच पर बैठे हुए हैं उनके ऊपर आंक्षेप नहीं करना चाहता हूं कि उन्होंने जो बिगाड़ा है स्थिति को, उसके बारे में चर्चा नहीं करना चाहते हैं। लेकिन इतना जरूर कह देना चाहते हैं कि जो दोनों ही समस्यायें हैं यह क्या सिर्फ बिहार सरकार और उसकी जो आय हैं उसके बूते के अन्दर की बात है कि उसकी पूर्ति कर सकता है तो मुझको कहना पड़ेगा...

श्री दिग्विजय प्रताप सिंह : सभापति महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ ऑर्डर है।

भारत सरकार ने जो पैसा दिया वह सिविल डिपोजिट में जमाकर देते हैं और खर्च नहीं कर पाते हैं।

सभापति : आप सरकार से पूछियेगा ।

श्री राज कुमार सेठ : सभापति महोदय, मैं सदन के सदस्यों से आग्रह करना चाहता हूं कि आप ऐसी योजना बनायें जो बिहार के बारे में हो क्योंकि हमारी समस्या कोई एक क्षेत्र के बारे में नहीं है, सम्पूर्ण बिहार के बारे में है । आज 1994-95 में सोच रहे हैं कि जलापूर्त्ति का शहरों एवं देहाती क्षेत्रों में अभाव है। आज ही इसकी चर्चा हो रही है ऐसी बात नहीं है। यहां बहुत से पुराने सदस्य बैठे हुए हैं। 30 वर्षों से यहां यह चर्चा होती रही है। जब बजट आता है तो इसके लिए सरकार को कोसते हैं।

(इस अवसर पर माननीय श्री इन्दर सिंह नामधारी ने अध्यासी सदस्य का आसन ग्रहण किया।)

सभापति महोदय, चाहे कांग्रेस की सरकार हो या दूसरे दल की सरकार हो या जनता दल की सरकार है । सभापति महोदय, हमारे माननीय सदस्य ने भारत सरकार की ओर इंगित किया है। मैं नहीं कहना

श्रीमती वीणा वादिनी पांडे : सभापति महोदय, माननीय सदस्य को आप कहें कि ये हिन्दी में अनुवाद करके बोलें, अंग्रेजी समझने में दिक्कत हो रही है।

सभापति : माननीय सदस्य, महासेठ जी, माननीय सदस्या कह रही है कि अंग्रेजी समझने में दिक्कत हो रही है। इसका हिन्दी अनुवाद करवा दीजिये ।

श्री राज कुमार महासेठ : सभापति महोदय, यह तो राज्यसभा का प्रोसिडिंग है।

(व्यवधान)

सभापति : शांति, शांति । आप लोग कृपया बैठ जाइये । हम सब लोगों को बोलने का मौका देंगे ।

श्री ओ० पी० लाल : सभापति महोदय, चूंकि आप आसन पर हैं, आपसे कहना चाहते हैं कि आज पानी की जैसी समस्या हो गयी है उस पर पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्य को अपना सुझाव, अपना विचार देना चाहिए। अगर आंकड़े के आधार पर बोलकर अपना समय बर्बाद करेंगे तो उससे जनता का कल्याण नहीं होने वाला है। इस बात को हमें सोचना होगा कि आज हिन्दुस्तान को आजाद हुए 47 वर्ष हो गये इसके बाद भी आज पटना जैसे शहरों में, छोटानागपुर के पठारी इलाकों में, संथालपरगना में खासकर पलामू, हजारीबाग गिरिडीह और धनबाद के इलाके में एक-एक बूंद पानी के लिए हमारी मां बहनें तरस रही हैं। कई लोग पलायन कर रहे हैं। पशुओं को पानी नहीं मिल रहा है। उनसे यह कहेंगे कि ...

सभापति : महासेठ जी, माननीय सदस्य की भावना यह ठीक है कि पक्ष और विपक्ष में बोलते हैं लेकिन जो सदन की भावना है उसको
18) देखते हुए अपनी बात को केवल आंकड़ों के जाल से न जोड़े । जल संकट से किस प्रकार मुक्ति पायी जा सकती है, इस पर विचार होना चाहिए।

श्री अनुप लाल यादव : सभापति महोदय, मेरी व्यवस्था है । आपने रूलिंग दे दिया कि माननीय सदस्य सदन की भावना को देखते

हुए पानी के सवाल को रखें । माननीय सदस्य यही सवाल उठा रहे हैं कि केन्द्र से बिहार को कितना पैसा मिला कितना नहीं मिला । हमारे मंत्री कहां से चापाकल लगवायेंगे इसी संबंध में ये बोल रहे है।

सभापति :माननीय सदस्य श्री अनूप लाल जी, मैंने कोई रूलिंग नहीं दिया है । मैंने केवल यह कहा है कि माननीय सदस्य की जो भावनायें हैं, उसको देखते हुये बोलिये । यह ठीक है कि पक्ष और विपक्ष के लोग अपने ढंग से बोलते हैं।

श्री अवध बिहारी चौधरी :सभापति महोदय, माननीय सदस्य श्री अनूप बाबू जो बोल रहे थे, उसी संबंध में मुझे भी कहना है। माननीय सदस्य आंकड़े देकर आंकड़े द्वारा बताना चाहते हैं कि हमारे संसाधन क्या है और माननीय सदस्यों की भावना जो है उसके मुताबिक महासेठ जी बोले। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि वे अपना विचार रखते हैं तो सदन की भावना और जो हमारे यहां समस्या है, सरकार की जो मजबूरियां है, जो आर्थिक अभाव है, उसके ऊपर बोलने का काम करते हैं ? यही मैं कहना चाहता हूं ।

सभापति :इस बात से मैं शत-प्रतिशत सहमत हूं। अगर इधर की भावना ऐसी है तो वास्तविक स्थिति ऐसी है, इस संबंध में भी बोलना चाहिये, इस विचार का मैं हूं ।

श्री विजय कुमार चौधरी :सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं और सदन को जानकारी देना चाहता हूं कि जलापूर्त्ति से संबंधित विभिन्न समस्याओं को सरकार के सामने रख रहे हैं। सरकार वाद-विवाद के क्रम में इसका उत्तर देगी। लेकिन समस्याओं के बारे में मंत्री महोदय से समय-समय पर अलग से सम्पर्क किये हैं, उसमें उन्होंने अपनी मजबूरियां व्यक्त की है, इस बात को वे अपने जवाब में कैसे बोलेंगे। इसलिये मेरा अनुरोध है कि माननीय सदस्यों को अपनी मजबूरियों और दिक्कत को कहने के लिये 5 मिनट का समय दिया जाय। मुख्यमंत्री कमीटमेंट करते हैं और पैसा इनको देते नहीं है। अभी 5-5 चापाकल गड़वाने की बात है, मुख्यमंत्री जी घोषणा कर दिये और वे कहते हैं कि पैसा नहीं है, हम कैसे करायेंगे ।

सभापति : यह तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ। अकेले में कोई बात वे कहते हैं तो आपको सदन में यह बात नहीं कहनी चाहिये ।

श्री राज कुमार महासेठ : सभापति महोदय, जिस बात की चिन्ता माननीय सदस्यों ने व्यक्त की है, उसी विषय पर हम बोल रहे हैं लेकिन, जो शंका है माननीय सदस्यों को, उसके बारे में मैंने पहले ही आंकड़ा दे दिया है। लेकिन इन आंकड़ों से मैं संतुष्ट नहीं हूं। 90-91 में इन मादों में जितना पैसा था, उससे ज्यादा पैसा इस बार रखा गया है, सुरक्षा की तरह पेयजल की समस्यायें बढ़ती जा रही हैं। शहरी क्षेत्रों में भी समस्यायें बढ़ी हैं इसलिये जो पैसा इनको मिल रहा है, वह नगण्य है। हम कैसे व्यवस्था कर सकते हैं। हमारा ध्यान जा रहा है केन्द्र सरकार पर, केन्द्र सरकार व्यवस्था करती है, इन मदों में दूसरे प्रान्तों के अन्दर पेयजल की समस्याओं के लिये, सड़क के उत्थान के लिये, शहरों के उत्थान के लिये । लेकिन बिहार के साथ केन्द्र का व्यवहार सौतेलापन का है। इसलिये हमारी प्रार्थना है कि पार्टी से ऊपर उठकर जब तक हमलोग पहल नहीं करेंगे, तब तक इस प्रदेश का कल्याण होने वाला नहीं है, यह हमारी अवधारणा है। जनता दल और कांग्रेस के लोगों को हमलोग दोष देते हैं, यह ठीक नहीं है। वास्तव में जो जटिल समस्यायें हैं, उसके लिये हमलोगों को एक हो करके जो से स्रोत मिल सकता है, जहां से हमलोगों को पैसा मिल सकता है, उसके लिये हमलोगों को निदान ढूंढना चाहिये। इसके लिए हमलोगों को उपाय करना होगा। इसलिये मैंने उदाहरण दिया है, सभापति महोदय क्या कारण है– केन्द्र ने जो चयन किया है, उसके बारे में बतलाना चाहता हूं कि :

"The Minister of State for Urban Development, Shri P.K. Thungon informed Shri Rajni Ranjan Sahu that the first Statutory quinquennial review of Regional Plan 2001
19) including the provisions relating to the development of human settlement in NCR, has commenced.

About 8218 acres of land has been acquired and 5390 acres developed in the towns of Meerut, Hapur, Bulandshahar, Khurja, Gurgaon, Panipat, Rewari, Rohtak, Dharuhera, Alwar and Bhiwadi."

लेकिन पटना, रांची, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा जिला को नहीं लिया गया है। इसलिये सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि आउट प्लान के ऊपर वहां पर कितना खर्च किया गया है।

सभापति :महासेठ जी और माननीय सदस्यों को कहना चाहता हूं कि कोई माननीय सदस्य बोलें तो स्टडी करके बोलें। अगर हरेक सदस्य पढ़कर आयेंगे तो इससे सदन की गरिमा बढ़ेगी ।

श्री राजकुमार महासेठ :सभापति महोदय, मैं पढ़कर नहीं आया हूं। हम यहां आये तो हमको बोला गया कि आपको आज बोलना है।

श्री कृष्णानन्दन झा : सभापति महोदय, ये तो राज्यसभा के क्वेश्चन का जवाब पढ़ रहे हैं।

सभापति : माननीय सदस्य कह रहे हैं कि आप क्वेश्चन का जवाब पढ़ रहे हैं, आपके द्वारा जितने नाम लिये गये हैं, सब हरियाणा शहर के हैं, क्या यह क्वेश्चन हरियाणा स्टेट से संबंधित था?

श्री राजकुमार महासेठ :यह क्वेश्चन बिहार के एम० पी० का है और ये कांग्रेस के एम० पी० हैं, उन्हीं को जवाब दिया गया है।

श्री कृष्णानन्दन झा :सभापति महोदय, महासेठ जी को पढ़ रहे थे, उसका क्वेश्चन क्या था, उसको वे पढ़ लें ।

सभापति :उसको आप पढ़ दीजिये। वह स्टेटमेंट है या गवर्नमेंट का जवाब है या किसी प्रश्न का उत्तर है।

श्री राजकुमार महासेठ :यह बिहार के एम० पी० का प्रश्न है

सभापति : क्वेश्चन क्या है ?

श्री राजकुमार महासेठ :क्वेश्चन यह है कि 2001 में रिजनल प्लान में इनक्लूजन हुआ है, उसमें कौन-कौन-सा शहर लिया गया है।

सभापति :सिन्स दी क्वेश्चन इज रेलिभेन्ट । ठीक है आप बोलिये।

श्री राजकुमार महासेठ : सभापति महोदय, हम यह देखना चाहते थे कि बिहार में जिन बातों को लेकर मांग पर खड़े हैं, इनकी

समस्या का निदान करना है तो ज्वाएंटली लड़ना पड़ेगा अपने अधिकारों के लिये और वहां तक जाना पड़ेगा। इसके लिये अगर हमारे पदाधिकारी दोषी हैं तो उन्हें डांटना पड़ेगा और अगर हमारे मंत्री है तो उनको भी कहना पड़ेगा । सदन अगर जवाबदेह है तो इसे भी अपनी भूमिका अदा करनी पड़ेगी। जब तक इन बातों को जोड़ कर नहीं कहेंगे तो समस्या का निदान नहीं होगा। सभापति महोदय, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि नेशनल सीटीज के बारे में जब क्वेश्चन हुआ, इसके अन्दर जिन शहरों को लिया जाना है मोपुलेशन के आधार पर, इसमें बिहार का नाम भी नहीं हैं सबसे ज्यादा तकलीफदेह बात यह है कि इम्पलीमेन्टेशन ऑफ एन० टी० पी० सी० स्कीम की चर्चा हुयी लोकसभा में और केन्द्र सरकार ने फ़ैसला दिया। इसको देखने से लगता है कि इसमें बिहार कहीं नहीं आता है। इस स्कीम के अन्तर्गत करोड़ों अरबों रुपया दिया विभिन्न राज्यों को लेकिन, इससे भी बिहार वंचित रहा है और हमारी सारी समस्यायें जो आज की मांग में हैं इससे संबंधित है। कोई भी समस्या मैंने ऐसी नहीं रखी है जो इससे भिन्न हो। इसलिये सभापति महोदय, माननीय सदस्यों ने जहां कहा है कि ...

सभापति : माननीय सदस्य टोनी जी, आप बैठे-बैठे क्यों बोल रहे है। आगे कुछ कहना है तो आप इशारा दीजिये, मैं बोलने का मौका दूंगा।

श्री राजकुमार महासेठ : अब सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि

सभापति : आप एक मिनट बैठ जाइये ।

श्री संजीव प्रसाद टोनी : सभापति महोदय, श्री राजकुमार महासेठ एक अनुभवी आदमी हैं और बिहार की जो समस्या है पानी की, बिजली की इस पर बोलें । यह केन्द्र सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। यह नहीं
20) देखते कि इनके दल के काफी एम० पी० है। वहां प्लानिंग कमीशन में जाना पड़ता है । यह डीबेट में केन्द्र सरकार पर दोष उठा रहे हैं। बिहार सरकार ने सारे पैसे को सिविल डिपाजिट में जमा कर दिया और एक भी काम नहीं किया। इन्होंने घोषणा किया 90-91 में कि 5-5 चापाकल देंगे प्रत्येक विधायक की अनुशंसा पर लेकिन एक भी नहीं हुआ। यह सिर्फ

केन्द्र सरकार पर आक्षेप लगा रहे हैं और इनकी सरकार कोई भी काम नहीं कर रही है।

सभापति : माननीय सदस्य राजकुमार महासेठ, आप कंक्लूड करेंगे और बोलेंगे ।

श्री राजकुमार महासेठ : हम पांच मिनट में कन्कलूड कर देते हैं।

सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं केन्द्र सरकार पर कोई दोषारोपण नहीं कर रहा हूं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जेनरल श्रोतों से हमें पैसा मिल सकता हैं उस पैसे से हमारी सरकार या हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने टेप किया है। अगर एन० टी० पी० सी० ने तय किया होता तो हमारी समस्यायें जो हैं वह समस्या नहीं रहती । यह बात जरूरी है कि बिहार सरकार ने अपने सीमित श्रोतों में, जो आज साधन है।...

सभापति :टोनी साहब, यह सदन में बीहैभ करने का तरीका नहीं है। सदन में व्यवस्था बनी रहे इसका ख्याल रहे ।

श्री राजकुमार महासेठ : मैंने तो अभी यह नहीं कहा है कि बिहार सरकार और हमारे पदाधिकारी ने पेयजल की संकट को बिल्कुल दूर करदिया है और कोई संकट हमारे यहां है ही नहीं। शहरी क्षेत्र में जो सुधार होना चाहिये इसमें गड़बड़ी हुयी है।

सभापति :महासेठ जी, आसन यह जिज्ञासा लेना चाहती है कि पिछले वर्ष बजट पर जो बहस चल रही थी, माननीय मंत्री पर भी इस पर ध्यान देंगे। सदस्यों के बहुत दबाव के बाद माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि हर पंचायत में 5-5 चापाकल माननीय विधायकों की अनुशंसा पर लगाया जायेगा । कम-से-कम रूलिंग के बारे में होना चाहिये । आपको तो पूछना चाहिये कि 5 में कितना लगा। यह आपको अधिकार है।

श्री राजकुमार महासेठ :अब मैं आ रहा हूं इस विषय पर । मैं ये कहना चाहता हूं कि जो चापाकल पिछले सुखाड़ के समय हमारे यहां और खासकर 80 प्रतिशत चापाकल बिल्कुल सूख गया था। उनका

उखाड़–गाड़ हुआ 93–94 में । इसमें सरकार की उपलब्धि मानी गयी। फिर भी मैं सरकार को यह राय देना चाहता हूं कि अभी जो पिछले सत्र में आपने कहा था कि 5–5 चापाकल हर पंचायत में देंगे लेकिन वह भी नहीं किया गया। दूसरी बात, सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी शहरी क्षेत्र के अन्दर पटना में पेयजल का जो संकट है इसके बारे में चर्चा हुयी है और सभापति महोदय, आसन ने जो निर्देश दिया इसको मंत्री महोदय और विभाग ने ग्रहण किया होगा। लेकिन मैं आपका ध्यान मधुबनी जिले के अन्तर्गत पेयजल की संकट और इसके निदान की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । हमारे यहां पाइप है, फिल्टर है लेकिन सभापति महोदय पैसा नहीं है, जिससे कि इन चापाकलों को गाड़ा जाय। सभापति महादेय, मधुबनी शहर बहुत पुराना शहर है जो आज जिला बन गया है और आधी आबादी को पेयजल की सुविधा मिल गयी है और आधी आबादी पेजजल की सुविधा से वंचित है। जो मांग आयी है इस पर भी सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है। मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि मधुबनी जिला में जहां पर पेयजल की सुविधा नहीं है वहां पर कम–से–कम आज 200 चापाकल की समस्या है, इसे दूर किया जाय। सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि देहाती क्षेत्र में सम्पूर्ण जिला में जहां–जहां वोरिंग करके वाटर सप्लाई किया गया था वहां 80 प्रतिशत बोरिंग फेल है और वाटर सप्लाई चालू नहीं है। मैं चाहूंगा कि सरकार इसको देखे। हमारा वहां इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार है लेकिन कहीं बिजली की वजह से, कहीं ट्रांसफार्मर की वजह से, कहीं बिजली का तार चोरी होने के कारण, जो हमारा चापाकल काम नहीं कर रहा है सरकार इसको देखे । मैं सरकार से इतना आग्रह करना चाहता हूं कि कम से कम मधुबनी जिला के अन्दर जितने भी चापाकल खराब हैं उनसे कम से कम 50 प्रतिशत चापाकल उखाड़–गाड़ कर दे ताकि हमारे समस्या
21) का निदान हो सके और बाकी जितने भी चापाकल बचे हैं उन्हें 2 महीने के अन्दर ठीक कर दे। मैं सुझाव के साथ मांग का समर्थन करता हूं ।

जय हिन्द ।

श्री बालिक राय : सभापति महोदय, जो कटौती प्रस्ताव पेश किया गया है, उनका मैं विरोध करता हूं । परन्तु साथ–ही–साथ यह भी

करना चाहता हूं कि आज बिहार के चाहे पटना शहर हो, गया शहर हो, औरंगाबाद हो, मुंगेर हो, हजारीबाग शहर हो, मैं कई शहरों गया हूं लेकिन देखता हूं कि शहरों की स्थिति नारकीय है। सड़क और नाला में कोई अन्तर नहीं रहता है।

रात में सड़कों के बीच में गड्ढे होते हैं, गया शहर के सड़कों के बीच में कई मेन होल हैं, उसमें कई महिला इसके अन्दर चली गयी हैं, तो इस तरह से पता नहीं आपकी सफाई का इन्तजाम है। आज गया शहर में छः महीने से हड़ताल चल रही है। वहां के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनके बारे मे कर्मचारियों ने कहा है, वहां के ज़िलाधिकारी ने इस एडमिनिस्ट्रेटर के खिलाफ़ लिखा है वे बहुत ही भ्रष्ट हैं, वहां के कुछ जमीनें हैं, नगर निगम के जो जमीनें हैं, उसको वे बेच रहे हैं, लीज पर दे रहे हैं। पहले तो इनका ट्रांसफर कर दिया लेकिन बाद में राजनीतिक दबाव के चलते और मुझको यह पता चला कि तीन लाख रुपये खर्च करके अपना स्थानान्तरण रूकवा लिये ।

श्री जगदीश शर्मा : सभापति महोदय, तीन लाख रुपये कौन लिया ?

श्री बालिक राय : सभापति महोदय, उन्होंने तीन लाख रुपये देकर के अपना स्थानांतरण रुकवा लिया।

सभापति : माननीय सदस्य श्री टोनी जी कृपया आप शांति के साथ बैठे रहें तो मै इसपर गंभीरता से विचार करूंगा ।

श्री बालिक राय : सभापति महोदय, क्या कारण है कि वहां के कर्मचारी पिछले 22 माह से हड़ताल पर हैं, वेतन नहीं मिला है ...

सभापति : आपने तो कहा, पैसा लेने वाले कौन हैं ?

श्री बालिक राय : सभापति महोदय, चर्चा है, मैं माननीय मंत्री को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मंत्री जी खुद जानते हैं इनके बारे में कि वे कितना भ्रष्ट हैं ...

सभापति : माननीय सदस्य श्री टोनी जी, आपका समय कट रहा है, आपने यह वचन क्यों दिया कि शांति से बैठेंगे ।

श्री बालिक राय :सभापति महोदय, नगर निगम के जो माननीय मंत्री हैं, इन्होंने भी कहा था कि ये भ्रष्ट हैं, इनको हटा देंगे लेकिन किस परिस्थिति में आप इनको रखे हुए हैं। ये अभी दो के चार्ज में हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटर के चार्ज में दूसरा डी० आर० डी० ए० अर्थात् डिस्ट्रीक रूरल डेभलपमेंट अथोरिटी के चार्ज में है। 30-35 लाख रुपये हुडको से मिला था गरीबों को मकान रिपेयर के लिए, उसका एक पैसा गरीबों को नहीं मिला, एडमिनिस्ट्रेटर ने आपसी बंदरबांट कर लिया गुंडों के माध्यम से । इस बात को जिलाधिकारी ने भी लिखा है और कई लोगों ने इनके बारें में लिखा है लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जांच करने से यह पता चल जायेगा कि उसको जो पैसा गरीबों के उत्थान के लिए, 30-35 लाख जो हुडको से मिला, उसका बंदरबांट हो गया। गरीबों से गुंडों ने बैंक ड्राफ्ट छीन लिए ।

सभापति महोदय, नगर निगम का तो यह हाल है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि गया नगर निगम के कर्मचारियों का पिछले 22 माह से वेतन नहीं मिला है, उनको वेतन दिलवाने का कष्ट करेंगे ।

दूसरी बात सभापति महोदय, गया शहर में दो-एक अंतर्राष्ट्रीय जगह है। पूरे हिन्दुस्तान के लोग और बगल में जो हिन्दू कंट्री हैं नेपाल के लोग भी वहां पिंडदान करने के लिए आते हैं लेकिन पिंड दान के अवसर पर गया शहर की जो स्थिति है, उसको देखकर हमलोगों का सर शर्म से झुक जाता है। बाहर से लोग पिंडदान करने अपने पितरों को तर्पण करने आते हैं, उनको नाला से होकर गुजरना पड़ता है, कोई सफाई की व्यवस्था नहीं रहती है, नाला और रोड एक रहता है । वे गाली देकर जाते हैं, बिहार की इस तरह की व्यवस्था को देखकर ।

सभापति महोदय, गया शहर में जितनी भी वाटर सप्लाई की पाईप
22) हैं, वे सभी फटे हुए हैं, इस कारण गया शहर में बड़े पैमाने पर पीलिया रोग, जौंडिस की बीमारी फैल रही है। वाटर सप्लाई के पानी पीने के लायक नहीं रहने के कारण बड़े पैमाने पर रोग फैल रहा है। इस तरह से एक-एक पाईप फटा हुआ है। जब सप्लाई का पानी बन्द हो जाता है तो पाईप के माध्यम से गंदा नाली का पानी जाता है और जब प्रेसर आता है तो नालों का गंदा पानी पहले मिलता है। इस कारण दो-दो बाल्टी शुरू

का गंदा पानी फेंक देते हैं यह सरकार आम जिन्दगी के साथ खिलवाड़ कर रही हैं जो सरकार लोगों को पानी नहीं पिला सकती है, वह सरकार लोगों को भोजन कैसे करा सकती है । अतः सरकार मिनिमम नीड्स, पानी की जो आवश्यकता है, लोगों को पानी पिलाने की व्यवस्था करे ।

सभापति महोदय, दूसरी बात आप जानते हैं कि गया शहर का दक्षिणी भाग पठारी इलाका है। वहां पर साधारण चापाकल नहीं गड़ सकता है। वहां रींग बोरिंग से ही चापाकल गाड़े जा सकते है। लेकिन इनके पास इतना पैसा है नहीं, इनके कार्यपालक अभियंता कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, जिससे मैं रींग मशीन मंगाकर बोरिंग कर सकूं। सभापति महोदय, इन्होंने पांच-पांच चापाकल दिया था, वे पांच चापाकल अभी गड़े नहीं है। और फिर ये कहते हैं कि एक चापाकल और देंगे, जब पहले का पांच चापाकल गड़ा ही नहीं तो एक चापाकल कहां से लगायेंगे ? दूसरे जिला में गड़ा है कि नहीं गड़ा, लेकिन गया जिले के बारे में मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि एक-भी चापाकल नहीं गड़े हैं तो पांच चापाकल के बारे में क्या कहूं। यह स्थिति है । आज जो गांव के लोगों को चापाकल दिये गये हैं सभापति महोदय, गांव के चापकल जो पहले गाड़े गये थे उनमें 90 प्रतिशत खराब हैं, इनका स्पेशल रिपेयर, साधारण रिपेयर करने की आवश्यकता है। लेकिन, जब रिपेयर के लिए पैसा नहीं देंगे तो रिपेयर का काम कैसे होगा । आज चापाकल की स्थिति ऐसी हो गयी है कि लोग उसमें जानवर और सुअर बांध रहे हैं। जानवर और सुअर बांधने का काम लिया जा रहा है इन चापाकलों से। जिन चापाकलों से पानी मिलना चाहिए, उस चापाकल से जानवर और सुअर बांधने के काम में लाया जा रहा है। इसलिए हम चाहेंगे कि सरकार पीने के पानी की व्यवस्था करे। गांव के गरीब लोग नदी का पानी पीते हैं, नाला और पहाड़ों का पानी पीते हैं, गया शहर के दक्षिण इलाके के लोग । इसपर सरकार ध्यान दें, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री कृष्णानन्द झा :सभापति महोदय, कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए मैं खड़ा हूं। मैं खासतौर से चापाकल, जो इस विभाग का मुख्य आकर्षण है, उसके संबंध में दो शब्द कहना चाहता हूं जब प्रारंभ में यह निश्चिय किया गया कि देश में जो बहुत बड़ी आबादी है, उनको

पेय जल की सुविधा नहीं है, उन्हें पेय जल आपूर्ति एक निश्चित अवधि के अन्दर किया जाय और उसमें एक साधन चापाकल का है। पहले कुआं पी० एच० ई० डी० डिपार्टमेंट की ओर से बनता था लेकिन, अब जलापूर्ति योजनाओं के द्वारा यह काम किया गया तब से चापाकल का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। तब से बड़े पैमाने पर प्रत्येक वर्ष में यह काम किया जा रहा है लेकिन, जो हमारे राज्य में किया जा रहा है, मैं महसूस करता हूं कि जो भौगोलिक स्थिति इस राज्य का है, उत्तर बिहार की और दक्षिण बिहार की, जहां उत्तर बिहार में 100 फीट के बाद पानी मिलना शुरू होता है वहीं दक्षिणी बिहार में 100 फीट के बाद पानी मिलना शुरू होता है लेकिन, दोनों के बारे में एक ही नीति, निर्णय यहां से किये जा रहे हैं।

उसका नतीजा यह हो रहा है कि अगर आंकड़े माननीय मंत्री जी देखेंगे तो दक्षिण बिहार में प्रत्येक वर्ष में 7 से लेकर 10 प्रतिशत चापाकल इनका फेल होता है, जहां पानी नहीं मिलता है लेकिन उसके पीछे पैसा विभाग ले लेती है और आज जो सबसे बड़ा प्रोबलम जो हो रहा है वह दक्षिण बिहार में तो हो ही रहा है लेकिन बहुत एलीमिंग सिचुयेशन यह है कि जिस तरीके से चापाकल गाड़े जा रहे हैं पिछले दो वर्षों में वाटर लेबल काफी नीचे जा रहा है और पिछले वर्ष की गर्मी में 80 प्रतिशत चापाकल तीन महीने में बिल्कुल बेकार हो गया, चूँकि उसमें पानी का सतह काफी नीचे चला गया है। इस तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है। सिर्फ एक फौरमेलिटीज हो रही है कागज पर कि हमने इस वर्ष इतना चापाकल गाड़ा और अगर इसके ऊपर सरकार गंभीरता से विचार नहीं कर रही है कि वाटर लेबल को कैसे मेंटेन करे तो कुऐं भी सूख रहे हैं और चापाकल भी जितने हैं सब बेकार हो रहे हैं।

सभापति : आप क्या सुझाव देना चाहते हैं ?

23) **श्री कृष्णनंद झा :** मेरा सुझाव होगा कि जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है थोड़ा इनको को–औरडिनेट करना चाहिए ताकि सतह पे वाटर लेबल रह सके। जब तक आप जल श्रोत को एक खास जगह पर नहीं रखेंगे तब तक आपका काम नहीं चलनेवाला है। सरफेस वाटर को इनको बढ़ाना होगा। दूसरी बात है कि जो इनका मैकेनिकल डिपार्टमेंट है और जो इनका बोरिंग डिपार्टमेंट है उसमें कोई

कोऔरडिनेशन नहीं है। देहातों में बोरिंग हो जाता है वह महीनों पड़ा रहता है। उस पर हेड लगाने वाला कोई नहीं रहता है चूँकि हेड लगाने का काम दूसरा विभाग करता है। कहीं हेड लग गया तो आज कई वर्षों से इस तरह के दर्जनों ऐसे उदाहरण हैं, जहां प्लेटफार्म नहीं बना है चापाकल का। एक और महत्वपूर्ण बात है कि हम सेफ परमानेंट वाटर दें लेकिन, मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं कि देहाती क्षेत्र में इनका प्लेटफार्म बनता ही नहीं है। जबकि पेमेंट होता है तो एक साथ तीनों का पेमेंट होता है और चापाकल गड़ गया वहां पर, पाइप 70-80 मीटर लगना चाहिए 40 मीटर 25 मीटर लगता है। कोई देखने वाला नहीं है। वहां कोई प्लेटफार्म नहीं बनता है। तो इनके विभाग में यह चीज होनी चाहिए जो को-औरडिनेशन कर सके। मैं खासतौर से माननीय मंत्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि शहरी जलापूर्ति योजनायें जितनी हैं और देहातों में जलापूर्ति योजनायें हैं उसमें नया तो इन्होंने चार वर्ष में एक भी नहीं बनाया लेकिन जितने पहले से कार्यरत थे उसमें से आज 80 प्रतिशत बेकार होकर बैठी हुई हैं । या तो कहीं मोटर जल गया है, वह रिपेयर करने वाला कोई नहीं है, कहीं उनका पंप खराब हो गया है, उसको रिपेयर करने वाला कोई नहीं है और जो एक साधन बना हुआ था लोगों को पेयजल मिलता था लेकिन इनके विभाग की निकम्मेपन की वजह से योजनायें बेकार पड़ी हुई हैं। मैं इसे जानना चाहूंगा कि जितनी संख्या है माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि कितनी शहरों में और देहाती क्षेत्र में जलापूर्ति योजनायें चल रही हैं और कितनी खराब हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं । देवघर में जो जलापूर्ति योजना बनाई गई उसमें सारा काम हो रहा था। विभाग ने बहुत पहले पैसा भी दे दिया लेकिन वह फंक्शन इसलिए नहीं कर रहा है कि इनका मैकेनिकल डिपार्टमेंट के जितने होर्स पावर का मोटर था उसके मुताबिक पंप लगाये नहीं और जब उसका रिभयु हुआ तो यह कहा गया कि उसमें पंप जो दिया गया है वह मोटर के हौर्स पावर से कम क्षमता वाला दिया गया है । इससे दुखद स्थिति और क्या हो सकती है। इनके विभाग के मैकेनिकल डिपार्टमेंट जो एक टेकनिकल डिर्पामेंट है उसकी लापरवाही से सारे पैसे खर्च होने के बावजूद भी लोगों को पानी नहीं मिल सके और उस पर भी विभाग से

कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं।

सभापति : श्री टेकलाल महतो अपना भाषण शुरू करें।

श्री टेक लाल महतो : सभापति महोदय, मैं ...

श्री युगेश्वर झा :सभापति महोदय, पांच-पांच चापाकल प्रत्येक पंचायत को देने की बात थी। एक भी चापाकल हमलोगों के एरिया में नहीं गड़ा है। इसलिए हम आसन से आग्रह करते हैं कि इसके बारे में सरकार से जवाब दिलाया जाय।

सभापति :झा जी उस समय आप सदन में नहीं थे। श्री राजकुमार महासेठ के भाषण के क्रम में मैने कहा था कि सत्ता पक्ष के लोगों को यह पूछने का अधिकार है कि सरकार द्वारा प्रत्येक पंचायत में पांच चापाकल देने की घोषणा हुई थी उसमें कितना लगा है। सत्ता पक्ष के लोगों का केवल यही कर्तव्य नहीं है कि वे तोता की तरह रटते रहें बल्कि सरकार की जो घोषणायें है उसका कितना कार्यान्वयन हुआ। मैं मंत्री जी को निदेश देता हूं आसन से कि वे अपने भाषण के क्रम में बताये कि जो सरकार की घोषणाएं एक साल पहले हुई थी उसके कार्यान्वयन का अनुपात क्या है, जो काम नहीं हुआ कौन जिम्मेवार है; कौन-सी मजबूरियां हैं यह स्पष्टतः उनको भाषण में बतलाना होगा ।

श्री लाल बाबू प्रसाद : सभापति महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में दो ब्लॉक है चिरईयां घोड़ासाहन । घोड़ासाहन मेरा निर्वाचन क्षेत्र है।

श्री रघुनाथ झा :सभापति महोदय, आपका निर्देश शिरोधार्य है। मंत्री जी जवाब देंगे। आप भी अच्छी तरह अवगत हैं। जो प्लान का साइज था वह कट हो गया और कारण से भिन्न-भिन्न डिपार्टमेंट का जो डिमांड
24) था, जो आश्वासन था और उसमें जो हमको पूरा करना था तो हमारे साथ कठिनाई हुई । इसका मंत्री जी अपने उत्तर में खुलासा करेंगे

श्री युगेश्वर झा : सभापति महोदय, 5-5 चापाकल ...

सभापति :आप कृपया बैठ जायें। जब मैं प्रत्येक माननीय सदस्य को कोई उंगली से भी थोड़ा इशारा करते हैं तो बोलने का समय देता हूं,

लेकिन इतनी शालीनता होनी चाहिए कि जब कहूँ कि बैठ जायें तो बैठ जाना चाहिए। श्री लाल बाबू प्रसाद ज़ी मैं आपको समय दे रहा हूं केवल दो तीन प्वायंट रखने के लिए, भाषण देने के लिए नहीं।

श्री लाल बाबू प्रसाद : भाषण नहीं दे रहा हूं।

सभापति : बतलाइये क्या कहना चाहते हैं ?

श्री लाल बाबू प्रसाद : सभापति महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में दो प्रखंड है चिरइयां और घोड़ासाहन। उसमें मैं सरकार से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि विधायक कोटा में कितना पाइप मिला और कितना पाइप गाड़ा गया, क्योंकि हमारा एलीगेशन है कि हमको जो पाइप दिया गया है विधायक कोटा में उसमें से हमसे कार्यपालक अभियंता लिस्ट लिया। लेकिन आधा पाइप नेपाल की तराई में बेच दिया। हमने 20 सूत्री में भी इस प्वायंट को भी उठाया। हमलोग जब जाते हैं तो न कभी ओभरशियर से भेंट होती है और न कभी एस० डी० ओ० से भेंट होती है। वे सब के सब मोतिहारी अपने घरों में रहते हैं। हम तो आग्रह करेंगे आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कि कार्यपालक अभियंता, ढाका जिसके अन्दर में घोड़ासाहन और चिरइयां प्रखंड हैं हमको कितना पाइप मिला है और कितना पाइप गड़ा है। यह मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इसका जवाब दिलवा दीजिए और जो रेस्ट पाइप बचा हुआ है हमको दिलवा दीजिए ताकि हमारे निर्वाचन क्षेत्र में पीने के पानी की सुविधा गरीब लोगों को मुहैया की जा सकें।

श्री टेकलाल महतो : सभापति महोदय, सरकार द्वारा जो बजट पेश किये गया है...

श्री प्रभुनाथ सिंह : सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि लाल बाबू प्रसाद सत्ता दल के सदस्य हैं और ये मंत्री जी से अलग मिलकर अपनी बात जान सकते थे और अपनी बात के क्रम में इन्होंने कहा कि इतना पाइप हमको दिलवा दीजिये। ये क्षेत्र के लिए नहीं मांग रहे हैं बल्कि पाइप बेचने वालों में शामिल हैं। पहले मांग रहे हैं पाइप तो क्षेत्र के लिए नहीं मांग रहे हैं, क्षेत्र के लिए पाइप मांगते तो बात होती इसलिए इनके लिए पाइप नहीं दिलवाया जाये।

सभापति : श्री टेकलाल महतो अपना भाषण जारी करिए ।

श्री टेकलाल महतो : सभापति महोदय सरकार द्वारा जो मांग प्रस्तुत की गई है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । सभापति महोदय, विज्ञान ने सिद्ध कर दिया है कि अन्न के बिना मनुष्य 7 दिन, पानी के बिना 3 दिन और हवा के बिना 2 दिनों तक जीवित रह सकता है। सभापति महोदय, झारखंड क्षेत्र का जहां तक सवाल है अन्न के मामले में सरकार ने उसको बर्बाद कर दिया है। पानी का जो श्रोत था, जो कुदरत के द्वारा दिया हुआ था, उसको भी सरकार ने बर्बाद कर दिया। देने को तो कुछ नहीं दिया झारखंड बेल्ट को इन्होंने बर्बाद कर दिया। सभापति महोदय, भारत सरकार और बिहार सरकार ने चाहे हजारीबाग हो, गिरिडीह हो, बोकारो हो, धनबाद हो, पलामू हो या रांची हो, हर जगह कल-कारखानें खुलवाकर जमीन को बर्बाद किया, जिसकी वजह से अन्न के बिना लोग मर रहे हैं, दाने-दाने को मोहताज हो रहे हैं । कल-कारखाने और उत्खनन होने के कारण वहां का जल स्तर काफी नीचे चला गया है। सभापति महोदय, रेहला में जो कास्टिक सोडा का कारखाना है उसके चलते जल प्रदूषण कितना हुआ है यह आपसे भी छिपा नहीं है। कुएं का पानी भी खारा हो गया है। झरिया, रैलीगढ़ा कोयला खनन के चलते वहां का जल स्तर काफी नीचे चला गया है। सभापति महोदय, अन्न की बात तो दूर रही पानी की जो व्यवस्था थी दामोदर नदी, जमुनियादी और पतरातू नदी सारी नदियों में कहीं सीमेन्ट फैक्ट्री की गंदगी गिराकर, कहीं क्लोरीन का पानी गिराकर, कहीं गोमिया एक्सप्लोसिव का पानी गिराकर नदियों को प्रदूषित कर दिया गया है और लोग वहां प्रदूषित जल पीने के लिये मजबूर हो रहे हैं। सरकार ने जो जलापूर्ति योजना की व्यवस्था की है उससे हम वंचित हैं। सभापति

25) महोदय, सरकार यदि जल की व्यवस्था समुचित और शुद्ध नहीं कर पाती है तो मैं कहना चाहता हूं कि हमारे यहां जो कुदरत का दिया हुआ, प्रकृति का दिया हुआ जल स्रोत था हमारे यहां जो शुद्ध पानी के झरने थे उससे हम पानी पीते थे लेकिन आज उत्खनन कार्य और कल-कारखानों के चलते उद्योग-धंधे बैठाने के चलते हमारा सारा प्राकृतिक जल स्रोत बर्बाद हो गया है। सरकार ने हमें दिया कुछ नहीं है सिर्फ बर्बाद किया है।

सभापति महोदय, मैं आज भी कहना चाहता हूं, गत वर्ष भी मैंने सुझाव के रूप में कहा था कि चापाकल की बात हमारे क्षेत्र में सरकार छोड़ दे। चापाकल की सरकार की जो योजना है उसमें आप देखियेगा कि एक टेंडर होता है, ठीकेदार दूसरा बोरिंग करता है। इस बात को जब बीस सूत्री और पंचायत समिति की बैठक में उठाते हैं तो जैसा कि आप सभी माननीय सदस्य भी जानते होंगे अगर हमलोग बोलते हैं तो कहते हैं कि यह मैकेनिकल का सवाल है, मैकेनिकल को जब कहा जाता है तो कहा जाता है सिविल का सवाल है। अगर हेड लग गया है तो कहा जाता है कि पाइप लगाने का काम हमारा नहीं है। पाइप लगा रहता है तो कहा जाता है कि प्लास्टर करना हमारा काम नहीं है। इसलिये मेरा सुझाव है कि चापाकल लगाना छोड़ दें । हमने गत वर्ष भी कहा था कि जहां 5 चापाकल लगाते हैं। उसके बदले वहां तीन कुआं ही खुदवा दें । इससे हेड लगाने का झंझट नहीं रहेगा। कुंआ रहेगा तो लोग बाल्टी से भी पानी निकालकर पी लेंगे। पी० एच० ई० डी० जो चापकल लगाने का काम करता है उसी को कहा जाय कि वह कुआं खोदवाये ताकि लोगों को पीने का पानी मिल सके ।

सभापति महोदय, हम 1885 से इस सदन के साथ हैं । प्रत्येक वर्ष प्रत्येक माननीय सदस्यों को पांच चापाकल का कोटा पंचायत के लिये मिलता था। फिर पांच की जगह तीन हुआ और फिर तीन की जगह एक हुआ। वह भी मंजूर होकर हमारे यहां नहीं गया है । महोदय, स्थिति यह है कि सबका रास्ता जाम हो जायेगा, सभी लोग घेरे जायेंगे। इसलिये मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से आग्रह करूंगा कि जो तीन चापाकल लगाने की घोषणा जो सदन में की गयी थी उसके लिये तुरंत राशि भिजवायें और साथ ही मैं यह भी कहना चाहूंगा कि आज फिर प्रत्येक माननीय सदस्यों को कम-से-कम पांच चापाकल और देने की बात करें । हम तो यहां तक कहना चाहते हैं कि तीन चापाकल की जगह पर दो कुआं ही हमारे यहां खुदवा दीजिये हम उसको स्वीकार कर लेंगे । इससे हमलोगों के लिये यह परमानेंट एसेट हो जायगा हम कुएं से पानी पीयेंगे और जरूरत पड़ेगी तो सिंचाई का काम भी करा लेंगे । इसलिये मै कहूंगा कि हमारे यहां 3 चापाकल की जगह दो कुआं ही खुदवा दें ।

सभापति महोदय, हमारे यहां मांडू जलापूर्ति योजना के लिये 18 लाख रु० यहां से हजारीबाग भेज दिया गया है। वहां के उत्तरी छोटानागपुर के कमीशनर को लेकिन, वहां के इनके जो अधीक्षण अभियंता और कार्यपालक अभियंता है वे इतने लापरवाह हैं कि विगत तीन वर्षों से वह पैसा सिविल डिपोजिट में पड़ा हुआ है। कभी बोलते है कि हम टेंडर करने जा रहे हैं। टेंडर हो गया तो कहते हैं कि मेकेनिकल टेंडर बनायेंगे, मेकेनिकल प्रस्ताव बन रहा है, कभी कहा जाता है कि सिविल प्रस्ताव बन रहा है, सिविल एस्टीमेट बन रहा है।

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ प्रसाद सोडानी :सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को एक सुझाव देना चाहता हूं एक आर्डिनरी चापाकल लगाने में छः से साढ़े छः हजार का प्राक्कलन बनता है, जबकि मनी भैल्यु करके बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी का चापाकल ढ़ाई हजार रु० में लगाया जा सकता है। अगर वह राशि विधायक को ही दे दी जाय तो विधायक लोग उस पैसे से बहुत बढ़िया क्वालिटी का चापाकल अपने क्षेत्र में गड़वा देंगे।

(व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश लाल : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो कहा कि ढ़ाई हजार रु० में चापाकल लग जायेगा जबकि छः से साढ़े छः हजार का प्राक्कलन बनता है। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे छोटानागपुर और संथालपरगना पहाड़ी क्षेत्र में एक चापाकल गाड़ने में 17-18 हजार रु० खर्च आता है।

सभापति :पलामू में तो बीस हजार रु० एक चापाकल पर पड़ता है।

26)

श्री ओम प्रकाश लाल : सभापति महोदय, माननीय सदस्य, सोडानी जी की मंशा अपने क्षेत्र के लिये हो सकती है। यह सभी जगह व्यवहारिक नहीं है।

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ झा : सभापति महोदय, यह क्या हो रहा है। सुझाव कभी यहां से आ रहा है कभी वहां से आ रहा है। मंत्री तो जवाब जब देंगे तो कहेंगे ही ।

सभापति : विचारों का मंथन हो रहा है।

(व्यवधान)

सभापति : माननीय सदस्य, श्री टेकलाल महतो जी, आप अपना भाषण कन्क्लुड कीजिये।

श्री टेकलाल महतो : सभापति महोदय, मेरा सारा समय तो बर्बाद हो गया टोका टोकी में।

सभापति : आपका समय बर्बाद नहीं हुआ है, आप अपनी बात कन्कलुड करें।

श्री टेकलाल महतो : सभापति महोदय, मैं कह रहा था कि 18 लाख रु० हजारीबाग में मांडू जलापूर्ति योजना का पड़ा हुआ है। मैं मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि वे अविलंब राशि विमुक्त कराकर मांडु जलापूर्ति योजना कों चालू करावें ।

सभापति महोदय, हमारे क्षेत्र के प्रखंड विशुनगढ़ जलापूर्ति योजना से आज तक एक बूंद पानी नहीं मिला । मुख्य अभियंता, श्री ललन सिंह पटना से वहां गये और ग्रामीणों की आश्वासन देकर आये फिर भी वहां के लोगों को आज तक पानी नहीं मिला ।

सभापति महोदय, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि हमारे अपने जिला प्रखंड में कोनार नहर का खुदाईकरण किया जा रहा है। नहर की गहराई 140 फीट है। कुआं मात्र 25, 30 है। सारे कूप एवं आहर सूख गये हैं और उसका जल स्तर नीचे चला गया है। सभापति महोदय, हमारे क्षेत्र में तापीन नार्थ, तापीन साउथ, परेज, फाकोडीह, बंजी, वेस्ट बोकारो, टुनी, केदला, कइयो, झारखंड, सारू, बेडा, आरा, कुजु, तोपा, पीन्डरा, तोयरा, खोद्य, होसिर, डाडी, गिछी, गिछी ए, गिछी सी, रेलीगढ़ा, रिकुवा, कलको, सुगिया, करमा प्रोजेक्ट तथा सांकी भरेचनगर में अनेकों हार्डकोक

है तथा छोटे–छोटे उद्योग लगने से जलस्तर नीचे चला गया है। इसलिए हम आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं।

सभापति :अब आपका समय समाप्त हुआ। माननीय सदस्य श्री मो० सिद्दीकी अपना भाषण शुरू करें।

श्री मो० सिद्दीकी : सभापति महोदय, मैं कटौती प्रस्ताव के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं जिस क्षेत्र से आता है, वह बारसोई क्षेत्र है, जो कटिहार जिला में पड़ता है। कटिहार, पूर्णियां, किसनगंज जो बिहार के पूर्वी क्षेत्र में है, वहां जो पानी की स्थिति है, वह काफी दयनीय है । वहां का पानी अशुद्ध हो गया है, वहां आयरन काफी है, जिसके कारण लोगों का पेट खराब हो रहा है, पेट खराब होने से तरह–तरह की बीमारी होती है, उस बीमारी से लोगों को अस्पताल में जाना पड़ रहा है। सभापति महोदय, हमारे जिला में पानी में आयरन को कंट्रोल करने के लिए उपाय किया जाय, ताकि लोगों को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हो सके। सभापति महोदय, ब्लीचिंग पाउडर देने से कोई फायदा नहीं होगा, उससे समस्या का समाधान नहीं होगा जब तक नीचे के पानी को कोई मशीन से या कोई टेकनोलॉजी के द्वारा शुद्ध नहीं किया जायेगा, तब तक इस समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। सभापति महोदय, हम आपके माध्यम से सरकार का ध्यान हमारे जिला में पेय जल की जो समस्या है, उसे ओर आकृष्ट करना चाहता हूं, ताकि जल्दी–से–जल्दी वहां पानी में जो आयरन है,उसको ठीक किया जाय, ताकि वहां के लोगों को शुद्ध पेयजल की सुविधा मिल सके। सभापति महादेय, हमारे क्षेत्र में एक ही सबडिवीज़न बना हुआ है, उस सबडिवीजन में जो सहायक अभियंता रहते हैं, वे सालमारी में रहते हैं, जो हमारे क्षेत्र से 8 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है और हमारे क्षेत्र में कोई समस्यी है तो हमलोगों को 8 किलोमीटर जाना पड़ता है, पानी पीने के लिए जो समस्या उत्पन्न होती
27) है, जो बंद ट्यूबवेल हैं, उसको चालू कराने के लिए हमलोगों को 8 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। इसलिए हम आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहेंगे कि सहायक अभियंता जो सालमारी में रहते हैं वे बारसोई में रहे, ताकि पीने कि पानी की जो समस्या उत्पन्न हो, उसका तुरंत समाधान हो सके। मैं सरकार का ध्यान

इस ओर आकृष्ट करना चाहूंगा कि सहायक अभियंता जो सालमारी में रहते हैं, वे बारसोई में रहे और बारसोई, बलरामपुर और कदमा में पीने के पानी की जो समस्या है, उसका अविलंब निराकरण हो सके। सभापति महोदय, हमारे यहां जो पेयजल का संकट है और वह पूर्वी क्षेत्र है, वहां जो 40, 42 साल पहले स्थिति थी, वही स्थिति आज भी है, आज भी वहीं संकट है। मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद जी इस संकट को जरूर दूर करेंगे, इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती प्रस्ताव का विरोध करता हूं और मांग का समर्थन करता हूं।

श्री संजीव कुमार टोनी :अध्यक्ष महोदय, मैं बनारस से आ रहा हूं।

अध्यक्ष : आप कृपया टू-दी प्वाइंट ही बोलें ।

श्री संजीव कुमार टोनी : सभापति महोदय, मैं कटौती प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं बिहार में अभी जो जल संकट की स्थिति बनी हुई है, उससे काफी लोगों की मृत्यु हो गयी है पानी के अभाव में ।

श्री लालू प्रसाद : कहां पर ?

श्री संजीव कुमार टोनी :गिनाता हूं। सभापति महोदय, लोगों को गंदे पानी पीने से हैजा हो गया, आंख में पीरी हो गयी ।

श्री लालू प्रसाद : कहां हो गया, बताईए न ।

श्री संजीव कुमार टोनी : अभी बिल्कुल नारकीय स्थिति बनी हुई है पूरे बिहार में। मुख्यमंत्री जी ने बड़े जोरों से कहा था कि गरीब-गुरबों के लिए और खास तौर पर हरिजनों के गांवों में पेय जल की व्यवस्था करेंगे, इन्होंने यह भी कहा था कि बिहार की बदहाली को देखते हुए हम गरीब और कमजोर तबके के लोगों को फर्स्ट फेज में चापकल देने का काम करेंगे, इसकी घोषणा की थी और कहा था कि बिहार में खुशहाली होगी। हरिजनों और कमजोर तबके के लोगों का स्वास्थ्य बनेगा। मगर आज भी जो गरीब लोग हैं, मुशहर हैं, उनके लिए इन्दिरा आवास योजना से, जो केन्द्र सरकार की योजना है, मकान बनाया जा रहा है, वहां पीने

के पानी की सुविधा नहीं दी जा रही है वहां जो हरिजन और मुशहर जाति के लोग रहने के लिए आते हैं, जो कम पढ़े–लिखे लोग हैं, वे नदी–नाले और कूओं का पानी पीकर मर रहे हैं, जिसकी सूचना मुख्यमंत्री जी के यहां नहीं है।

श्री लालू प्रसाद :सभापति महोदय, इनको हरिजन और मुशहर लोगों से मुलाकात भी होती है ?

श्री संजीव कुमार टोनी :सभापति महोदय, मैं एक गरीब परिवार से आता हूं। पूरे बिहार में मुख्यमंत्री जी मेरे बारे में गलत प्रचार कर रहे हैं।

सभापति : टोनी जी, असल में आपकी सेहत देखकर लोगों को गलतफहमी हो जाती है।

श्री संजीव कुमार टोनी : सभापति महोदय, असल बात यह है कि मैं बराबर खुश रहता हूं और कभी किसी चीज की परवाह नहीं करता हूं।

सभापति : आपकी सेहत का राज यही है।

श्री संजीव कुमार टोनी :सभापति महोदय, मेरे घर में सभी लोग दुबले हैं मेरा ही शरीर तंदरुस्त हो गया है।

श्री राजकुमार महासेठ :सभापति महोदय, माननीय सदस्य का गला बैठा हुआ है, इसके लिए लौंग खा लें तो अच्छा रहेगा ।

श्री लालू प्रसाद : सभापति महोदय, इनका गला ही नहीं फंसा हुआ है, ऊपर से लेकर नीचे तक फंसा हुआ है।

सभापति :इनका मैं इसलिए लिहाज करता हूं कि माननीय सदस्य
28) की शादी मेरे ही क्षेत्र में हुई है।

(व्यवधान)

श्री संजीव कुमार टोनी :सभापति महोदय, आज हम चुनाव के मौके पर जाने के लिए तैयार हैं।

सभापति : आपकी यह पहली शादी थी न ?

श्री संजीव कुमार टोनी : जी सर ।

सभापति जी, अब हमलोग चुनाव के मैदान में जाने के लिए तैयार है। मैं बड़ी गंभीरता से आज सदन की कार्यवाही सुन रहा था। मुझे लगा कि लोग ईमानदारी से बिहार के बारे में और गांव में रहने वालों के बारे में, उनके दुःख तकलीफ और उनकी सुख–सुविधा के बारे में चिन्ता करेंगे। परन्तु उसके बारे में किसी का ध्यान वास्तविक रूप में सदन को आकृष्ट करने के लिए नहीं हुआ।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि सदन के समक्ष किन्हीं माननीय सदस्यों ने इन समस्याओं के बारे में गंभीरता से मामला नहीं उठाया। पटना और बड़े–बड़े शहरों के नागरिकों के संबंध में काफी चर्चा की गयी लेकिन, जो गांव में रहने वाले लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके बारे में कोई नहीं बोल सके। मुख्यमंत्री जी जब गद्दी पर आये थे, तो व्यक्तिगत रूप से मैं खुश हुआ था कि अब जो गरीब, पिछड़े, हरिजन और मुशहर लोग हैं, उनके लिए सुविधा और खुशहाली बहाल होगी ।

मगर चार वर्ष हुए हैं मगर एक भी चापाकल नहीं गड़ सका है। महोदय, विधायक कोटा का जो पांच–पांच चापाकल की घोषणा हुई थी वह भी आज तक नहीं गड़ सका है, जनता दल के शासन में । महोदय, मंत्री जी बहुत सज्जन हैं। पी० एच० ई० डी० में माफिया गैंग है और वहां एक अलग ही सरकार चलती है। बड़े पैमाने पर चापाकल के नाम पर लूट हो रही है। हमारे क्षेत्र में 1990 में ए० आर० पी० का 46 चापाकल आया था, मैंने कलक्टर को, विभाग के मंत्री को, सेक्रेटरी को लिखा कि आपके अभियंता चोरी कर लिये है, लेकिन अब तक कुछ भी नहीं हुआ है। कोई कार्रवाई उन पर नहीं हुयी है। महोदय, ऐसे काफी लोग हैं, मैं उनका नाम भी बताऊंगा, उनलोगों पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुयी है। मनचाहा पोस्टिंग आज भी उन लोगों की हो जाती है। मैं मानता हूं कि मंत्री जी नहीं चाहते होंगे, मगर एक पार्टी में रहने के चलते कोई परिस्थिति आती होगी। दबाव में लोगों को खुश करने के लिए, आज भी देखते हैं

कि वे सभी अभियंता आज भी अच्छे पदों पर है। हुजूर मेरा यही कहना है कि आज जो स्थिति बन रही है, बिहार की, बिहार के लोगों की उम्मीद बन रही है, बिहार के लोग बीमारी की हालत से मर रहे हैं, पानी के अभाव में मर रहे हैं, सरकार को इस पर चिन्तित होना चाहिए और सरकार को शीघ्र पानी की व्यवस्था कराकर उन्हें रोग मुक्त बनायें।

सभापति महोदय, भारत सरकार बराबर पैसा देती रही है। ये लोग प्लानिंग कमीशन में जाया करते थे, मुख्यमंत्री जी जाते हैं, इनके सचिव जाते हैं, मगर पैसा तो इनका वेतन बांटने में, बिहार के रख-रखाव में और सिविल डिपोजिट में रखने में चला जाता है। हुजूर, मुझे उम्मीद नहीं है कि गांवों में जो पानी का संकट है वह कभी दूर नहीं हो सकता है। सभापति महोदय, विधायक जो सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले लोग हैं, जब भी हमलोग गांवों में जाते हैं, लोग पूछते हैं कि आप का दिया हुआ चापाकल नहीं गड़ा है, बहुत अफसोस होता है कि चापकल विधायक कोटा का हम पंचायतों में नहीं दे सके हैं। मगर मुख्यमंत्री जी बड़े जोर से भाषण देते हैं हुजूर, हम नहीं बोलते हैं, इनके पास सी० आर० पी०, बी० एस० एस० वाले रहते हैं, हम गरीब, कमजोर लोग हैं, डर लगता है। लेकिन इतना कहना चाहता हूं कि बिहार के लोगों को धोखा देने का काम नहीं कीजिये। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि आनेवाले दिनों में आप सबों को जनता को हिसाब देना होगा। गरीब गुरूआ हरिजन के हाथ उठेंगे तो आपको माफ नहीं करेंगे। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि केन्द्र सरकार के पैसे का दुरूपयोग किये हैं इसलिए केन्द्र सरकार आगे पैसा नहीं दे रही है। रुपया दिया था तो आपने सिविल डिपोजिट में रख दिया, दूसरे-दूसरे मदों में खर्च कर दिया। प्लानिंग कमीशन के चापाकल के लिए रूपया दिया था, बड़े पैमाने पर दक्षिण बिहार, मध्य बिहार में जो पैसा आपको खर्च करना था
29) वह आपने नहीं किया है। इसलिए सभापति महोदय आपके ऊपर ही हमलोगों को भरोसा है। सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि लालू जी के नेतृत्व में जो माफिया लोग है। उन पर मुकदमा होना चाहिये।

सभापति : टोनी जी। आपको ऐ खुशखबरी देना चाहता हूं कि आपके ससुर के घर के पास अपने कोटे का एक चापाकल दे दिया है।

श्री गुरुदास चटर्जी : सभापति महोदय, संथालपरगना और छोटानागपुर में जो पहाड़ी क्षेत्र है, जहां चापाकल गाड़ना है, वहां 60 प्रतिशत चापाकल असफल साबित हो रहे हैं।

सभापति :आपने क्या कहा? जितने चापाकल बोर हुए उसमें से 60 प्रतिशत असफल हो गये ।

श्री गुरुदास चटर्जी : सभापति महोदय, 30 प्रतिशत असफल और 30 प्रतिशत खराब हो गये हैं कुल 60 प्रतिशत चापाकल खराब हो कर पड़े हुए हैं। सरकार का उद्देश्य है जनता को पानी दे लेकिन, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जिस जगह पर चापाकल असफल हो रहे हैं उन जगहों पर दूसरे चापाकल नहीं गाड़े जा रहे हैं। धनबाद में एक चापाकल पर 16 हजार, 18 हजार रुपये खर्च आता है।

सभापति महोदय, दूसरी बात है कि धनबाद जिला में पानी का लेवल नीचे चला जा रहा है। निरसा प्रखंड में तीन जलापूर्ति योजनायें- निरसा, चांडा और चिरकुंड है। एक समय था जबकि वहां की आबादी पांच हजार थी और आज डेढ़ लाख हो गयी है लेकिन, आज भी जलापूर्ति योजना वही है, जो आज से तीस साल पहले थी। सरकार के पास पैसा नहीं है जो पाईप चेंजकर सके और न स्कीम है कि अलग ढंग से सोचे।

महोदय, ई० सी० एल० से लड़ाई करके "मैथन से लेकर खड़िया तक" के लिए 57 लाख रुपये की योजना पी० एच० ई० डी० को 8 महीना पहले भेज दी गयी थी। मार्च तक वह स्कीम पूरा होना था। पी० एच० ई० डी० को पांच बार पत्र लिखा गया, एक पत्र का भी जवाब नहीं आया और उसे आज तक पूरा नहीं किया गया है। अधूरा काम करके पी० एच० ई० डी० शेष राशि को खाने की बात सोच रहा है । इसीलिए हमने कहा था कि हमारे यहां चापाकल सक्सेसफूल नहीं है, दूसरा पानी का श्रोत नहीं है, थोड़ा बहुत जो अधूरा काम है उसको पूरा करें ।

सभापति महोदय, महुदा में पी० एच० ई० डी० का एक स्कीम है। वहां लाल बत्ती जलाकर मंत्री जी गये, स्कीम का उद्घाटन कर दिये, परन्तु आपको सुनकर आश्चर्य होगा उसमें रात भर पानी ड्राम से भर कर

उद्घाटन करा दिया लेकिन आज तक वह स्कीम चालू नहीं हुई उस समय मंत्री श्री ओ० पी० लाल थे ।

सभापति : माननीय सदस्य ओ० पी० लाल बैठे हुये हैं। माननीय सदस्य आप पर आरोप लगा रहे हैं। क्या यह बात सही है ?

श्री ओ० पी० लाल : बिल्कूल सही है । आज तक वह स्कीम चालू नहीं हुई है।

सभापति, : मैं आपकी साफगोई पर अपनी प्रशंसा व्यक्त करता हूं।

श्री रघुनाथ झा : उद्घाटन कैसे हुआ ? हमलोग ऐसी स्कीम का उद्घाटन नहीं करते हैं।

सभापति : असल में दिक्कत यह है झा जी कि गद्दी से हटने के बाद आपके सामने भी उदाहरण आयेगा । अभी नहीं आयेगा ।

श्री गुरुदास चटर्जी : सभापति महोदय, पी० एच० ई० डी० विभाग की यह स्थिति है कि कहीं बोरिंग हुआ है तो कहीं लोअरिंग नहीं हुआ है, कहीं चापाकल गाड़े गये हैं तो कहीं प्लेटफार्म नहीं बना है। जब मेकेनिकल को पकड़ते हैं तो वह कहता है कि यह सिविल का है । इस तरह से यह विभाग पांच विभिन्न भागों में बंटा हुआ है, जिसको एक जगह करने की आवश्यकता है। इसलिए हम आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करते हैं कि इन सभी को समाप्त कर इसको कम-से-कम पंचायत के हाथ में दे दें तो कम-से-कम जनता के पास पानी पहुंच जायेगा।

श्री मानिक चन्द राय : सभापति महोदय, मैं कटोती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। सभापति महोदय, राज्य सरकार ने जल संकट की योजना पर अमल नहीं किया है, जिसके चलते आज
30) गांवों में और शहरों में पानी की समस्या बनी हुई है। सभापति महोदय, सही बात तो यह है कि जो लोग आज हां कक्ष में हैं वो कभी ना कक्ष में थे और जो आज ना कक्ष में हैं वो कल हां कक्ष में थे । और जब हम उधर थे तो हम भी अपनी सरकार की प्रशंसा करते थे और आज भी जो लोग उधर हैं सही बात कहना नहीं चाहते हैं। माननीय सदस्य श्री राज

कुमार महासेठ महाशय बोल रहे थे । मैं बड़े ही ध्यानपूर्वक उनकी बातों को सुन रहा था। इसलिए कि इधर-से-उधर चले गये हैं सरकार की विफलताओं पर और जानते हुए भी बोलना नहीं चाहते हैं । वे गांवों से आते हैं और हम भी गांवों से आते हैं। बिहार गांवों का राज्य है और इस राज्य में 67 हजार 566 गांव है और पानी को लेकर गांवों की स्थिति बड़ी ही विचित्र है। आज भी गांवों में गरीबों के यहां पानी की समस्या है। हमारे मुख्यमंत्री जी गरीबों की बात करते हैं, नारा देते हैं। भैंस चराने वालों, सुअर चराने वालो, मुर्गा पकड़ने वालों, चूहा पकड़ने वालों की बात करते हैं। आज उनके यहां पानी की समस्या है। सभापति महोदय, हम भी गांवों में जीतकर आते हैं, हमारे माननीय सदस्य बैठे हुए हैं। हमलोग भी कहीं न कहीं धनवान लोगों के हाथों बिक गये हैं। आज जब हम गरीबों के बीच पाइप बांटने की योजना बनाते हैं तो जो सफेदपोश लोग हैं, वे गरीबों का पाइप ले लेते हैं।

सभापति : माननीय मंत्री वर्मा जी, आप आसन की ओर पीठ करके बैठे हुए हैं। आप सदन की ओर मुंह करके बैंठे ।

श्री मानिक चंद राय : सभापति महोदय, मैं कह रहा था पानी का संकट चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे जनता दल की सरकार हो, पानी का संकट हमेशा रहा है। 1971-72 में सरकार ने यहां के 67 हजार गांवों का सर्वेक्षण करवाया कि आखिर गांवों में चापाकल या पानी के अन्य स्रोतों की व्यवस्था हुई है या नहीं तो 39741 गाँव ऐसे पाये गये जहां पीने के पानी की समस्या है।

श्री राजकुमार महासेठ : माननीय सदस्य कह रहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री चूहा पकड़ने वालों का नारा लगाते हैं । तो वो सिर्फ नारा ही लगाते हैं या करते भी है । जो करते हैं वो भी बोलें ।

श्री मालिक चन्द राय : सभापति महोदय, मैंने कहा कि वे चूहा पकड़ने वाले, मुर्गी पकड़ने वाले की बात करते हैं लेकिन उनके यहां पानी की समस्या है, उनको पेयजल नहीं मिलता है।

श्री शकील अहमद : सभापति महोदय, चूहा पकड़ने वाले जो हैं, उनमें राजकुमार महासेठ जी का नाम भी है, क्योंकि उनके पास गोदाम है, जिसमें बहुत चूहे घुस जाते हैं और वे इनको पकड़ते हैं।

श्री प्रभुनाथ सिंह :सभापति महोदय, आप आसन से निर्देश कर दें कि चूहा पकड़ने वालों की संख्या कितनी है इसका पता लगाया जाय और इस काम को करने का ठेका राजकुमार महासेठ जी को दिया जाय।

सभापति : एक बार 1980-81 की बात याद आती है, जब सरकार का निदेश गया था कि हर प्रखंड में चूहों की संख्या कितनी है इसका पता लगाया जाय और अब चूहा पकड़ने वालों की संख्या कितनी है, इसका भी मर्दनसुमारी हो जाना चाहिए।

श्री मानिक चन्द राय : सभापति महोदय, आज गांवों की जो स्थिति है लोगों को कुओं का पानी पीना पड़ता है और मवेशी धोने और स्नान करने के लिए नदी और पोखरे का काम लेते हैं। जो ज्यादा गरीब हैं और गरीबी रेखा के नीचे हैं, वे लोग पीने का पानी दूर-दूर से लाते हैं। बरसात का पानी कुआं में जाता है, जिससे उसमें कीड़े पड़ जाते हैं लेकिन, पी० एच० ई० डी० विभाग की तरफ से और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो कार्यकर्ता हैं वह गांवों में नहीं जाते हैं और वर्षों से कीटनाशक दवाइएं कुएं में नहीं डाले जाते हैं और वही दूषित जल गरीबों को पीना पड़ता है। तो सभापति महोदय, गांवों में जाते हैं, आप भी गांवों में जाते होंगे, गरीब लोग जो आज खाते हैं तो दूसरे टाईम के लिए भगवान का भरोसा करते हैं, उनके लिए भी पानी की आवश्यकता होती है। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था कि विधायकों की अनुशंसा पर प्रत्येक पंचायत में पांच चापाकल दिए जायेंगे लेकिम पांच से तीन हुआ और तीन से दो हुआ और दो चापाकल भी किसी पंचायत में नहीं गाड़ा जा सका है।

सभापति : माननीय संसदीय कार्यमंत्री, आप सदन को रास्ता दिखाने वाले हैं। मैं चाहूंगा कि आप अपनी सीट पर बैठ जायें।

(31) **श्री रघुनाथ झा** :आपकी आज्ञा सिरोधार्य है लेकिन, विरोधी पक्ष के लोगों से सदन ठीक से चलाने के लिए संबंध रखना ही पड़ता है।

सभापति :आपका जवाब बड़ा ही माकूल है, संसदीय कार्यमंत्री का काम मल्टी डाइरेक्शनल है।

श्री मानिक चन्द राय :सभापति महोदय, मैं अपने क्षेत्र सिवान जिला के बसंतपुर के बारे में कहना चाहता हूं। वहां के पी० एच० ई० डी० के कार्यपालक अभियंता, एस० डी० ओ० और जूनियर इंजीनियर तीनों मिलकर घोटाला कर रहे हैं। मैंने कई बार माननीय मंत्री से कहा लेकिन आज तक कार्रवाई नहीं हुई है।

सभापति महोदय, मैं पटना के हाईकोर्ट के गेट के नजदीक 140 नंबर फ्लेट में रहता हूं उसकी नारकीय स्थिति देखकर तो कोई भी कहेगा कि यहाँ मवेशी भी नहीं रह सकता है। माननीय मंत्री से और उनके विभागीय अधिकारियों से कहने के बावजूद टंकी की सफाई आज तक नहीं हुई है। कल भी मैंने लिखकर इसके बारे में दिया है और जब से सदन चल रहा है तब से कई बार लिखकर दिया है। एक साल के अन्दर इनके विभाग के कर्मचारियों को करीब एक हजार रुपये भी मैंने इसके लिए दिया है, लेकिन इनके विभाग के कर्मचारियों ने पैसा लेने के बावजूद काम नहीं किया है।

सभापति : माननीय मंत्री, जिस बिन्दु की ओर माननीय सदस्य ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, क्या यह मामला आपके सामने लाया गया है।

श्री मानिक चन्द राय :इनके विभाग को दिया, लेकिन विभाग का पदाधिकारी कोई सुनने वाला नहीं है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से दो-दो बार लिखवाया और विभाग को दिया लेकिन विभाग के पदाधिकारी कुछ भी ध्यान नहीं देते हैं।

श्री लालू प्रसाद : हो सकता है पदाधिकारियों को गलतफहमी हुई होगी कि आप मुख्यमंत्री के साथ हैं या नहीं । आपको बोल देना चाहिए था कि हम वहां जा रहे हैं।

श्री मानिक चन्द्र राय :सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री और विभाग का ध्यान फ्लैट नम्बर 140 की ओर ले जाना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि मेन टंकी को मरम्मत करवा दिया जाये और नाले को मरम्मत करवा दीजिए ।

डा० शकील अहमद : सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री और मंत्री, पी० एच० ई० डी० यहां बैठे हैं, मेरा उनसे आग्रह है कि विधायकों को अप्रतिष्ठित करने का प्रयास नहीं करे। विधायक कोटा का जो चापाकल मिलता है, वह नियमित रूप से मिले या सदन में घोषणा हो जाए कि यह कोटा बंद कर दिया गया है। 1992-93 के बारे में चापाकल की चिट्ठी गई है। माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी पांच के बारे में, और हर वर्ष घोषणा करते जा रहे हैं। जब हम क्षेत्र में जाते हैं तो जनता हमसे पूछती है कि बिहार के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है और हम कहते हैं कि वे गलत घोषणा किये थे तो जनता कहती है कि उनको क्यों नहीं पकड़ते हैं । इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि विधायकों का कोटा नियमित रूप से दें या इस कोटा को समाप्त कर दें, वापस कर दें।

सभापति : आप सदन में बहुत कम रहते हैं।

(व्यवधान)

मेरी बात आप सुनेंगे । यह मामला कई बार उठा। मैं आसन से इसकी रूलिंग दी कि माननीय मंत्री इस बात की स्पष्ट घोषणा करें कि जो पांच चापाकलों की घोषणा हुई थी उनमें कितने लगे, कितने नहीं लगे, और नहीं लगने का क्या कारण है, ये सारी बातें हो चुकी है।

श्री चन्द्रदेव प्रसाद हिमांशु :सभापति महोदय, दिल्ली से जनसत्ता अखबार आज नहीं आया है। मालूम हुआ कि हवाई जहाज से वह बंडल दो-तीन आदमी, जिसमें कुछ वरिष्ठ लोगों के बेटे की चर्चा है, ले गये । मैं सरकार से जानना चाहूंगा, सरकार से मांग करना चाहता हूं, केन्द्रीय मंत्री के बेटे हैं, इस तरह से केन्द्र से अखबार आये और उसकी लूट-पाट जारी होगी, और हमलोग यहां चुप-चाप बैठे रहें, तो यह अच्छी बात नहीं है।

32) **सभापति** : उस अखबार में कुछ खास न्यूज था क्या ?

(व्यवधान)

श्री अम्बिका प्रसाद : सभापति महोदय, मुख्यमंत्री जी कम-से-कम जांच कर हमलोगों को इतनी खबर दें कि बंडल-का-बंडल अखबार लूट ले, आखिर क्या बात थी ?

श्री लालू प्रसाद : वे तो हाथ में अखबार लिए हुए हैं, पढ़े ।

श्री चन्द्रदेव प्रसाद हिमांशु :“विमान में मंत्री के बेटे पर शराब के साथ सत्ता भी सवार थी” इस शीर्षक ने जनसत्ता को लूटवा दिया ।

सभापति : हिमांशु जी, अब आप बैठियें।

श्री प्रभुनाथ सिंह : पढ़वा दिया जाए, हमलोग भी सुन लें ।

श्री चन्द्रदेव प्रसाद हिमांशु : जनसत्ता संवाददाता ।

नई दिल्ली, 11 जुलाई । गुलाम नबी आजाद ने अंतर्देशीय उड़ानों में शराब पड़ोसने पर पाबंदी भले ही लगा दी हो पर अपनी ही इंडियन एअरलाइंस में वे शराब के नशे मे धुत होकर आने वालों पर रोक नहीं लगा सके हैं। भला लगाएं भी कैसे ? फिर उनकी पार्टी के मंत्री और उनके बेटे को सफर करने का मजा ही कहां आएगा ? हालांकि हरियाणा के मख्यमंत्री अपने ही एक मंत्री को इंडियन एअरलाइंस की उड़ान में शराब के नशे में एअर होस्टेस के साथ बदतमीजी के आरोप में मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर चुके हैं पर शनिवार की रात नरसिंह राव सरकार बचाने के लिए मशहूर मंत्री रामलखन सिंह यादव के बेटे ने सत्ता और शराब के दोहरे नशे का पराक्रम दिखा गया। (शेम, शेम)

सभापति : अब आप बैठ जाएं ।

श्री रघुनाथ झा : सभापति महोदय, इनका पूरा सुन लिया जाएं जो भी दोषी हो, हमारे दल का हो तो हम कार्रवाई करेंगे, उनके दल का हो तो वो कार्रवाई करें । मेरे दल का होगा तो हम कार्रवाई करेंगे ।

श्री चन्द्रदेव प्रसाद हिमांशु :“ये जनाव तो खुद को ही रामलखन सिंह यादव बता रहे थे लेकिन बाद में रसायन व उर्वरक मंत्री के निजी स्टाफ ने उन्हें पहचानने पर बताया कि वे उनके पुत्र प्रकाश चंद्र उर्फ बेबी हैं, जो बिहार के सांसद भी रह चुके हैं। शनिवार की रात जो बंबई से आई० सी० 183 में चढ़े तभी बुरी तरह लुढ़क रहे थे। उनके दो दोस्तों ने उन्हें सहारा देकर विमान की सीढ़ियों पर चढ़ाया था और जैसे ही विमान ने टेक ऑफ किया तो वे सीट में बेल्ट बांधकर बैठने की जगह बीचो–बीच खड़े हो गए ।

सभापति : अब आप बैठ जाइये, बैठ जाइयें ।

श्री लालू प्रसाद : महोदय, यह जानकारी मुझे मिली है कि दिल्ली हवाई अड्डे से और पटना हवाई अड्डे से, जो अखबार "जनसत्ता" आया है, उसमें कोई खबर छपी है, जिसके चलते पूरा बंडल गायब कर दिया गया है, चाहे पैसा देकर या जिस तरह से हुआ हो । महोदय, मैं जानकारी प्राप्त कर रहा हूं कि किस वजह से जनसत्ता को गायब किया गया है, क्या खबर उसमें छपी है, क्या सच्चाई है, उसको फैक्स से हमलोग मंगवा रहे हैं। कल हाउस में मैं इसका बिल्कुल जवाब दूंगा। उसमें जो भी लोग दोषी होंगे, ऐसी बात होगी, तो हम सख्त-से-सख्त कार्रवाई करेंगे।

श्री चन्द्रदीप सिंह : सभापति महोदय, मंत्री जी के प्रतिवेदन में यह बतलाया गया है कि सप्तम पंचवर्षीय योजना के अंत तक 250 व्यक्ति पर एक-एक जल श्रोत की व्यवस्था करने में हम सक्षम नहीं है। इसलिए हम समझते हैं कि जो विभाग, जो सरकार सक्षम नहीं है, वैसे सरकार के मांगों का समर्थन करना बहुत ही बेईमानी होगी। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि पिछली बार हमारे मुख्यमंत्री जी ने इसी सदन में ऐलान किया था कि हम प्रत्येक माननीय सदस्यों के क्षेत्र में प्रत्येक पंचायत में 5-5 चापाकल की व्यवस्था करेंगे । लेकिन बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस सरकार ने जलापूर्ति विभाग ने 92-93 में मात्र 1-1 चापाकल की व्यवस्था किसी प्रकार कर पायी है। सभापति महोदय, आप भी जानते हैं यह सरकार विभिन्न मोर्चों पर विफल रही है। सभापति महोदय, हमारे जिले भोजपुर में आरा जो शहर है वह नारकीय बना हुआ है।

श्री दशरथ कुमार सिंह : सभापति महोदय, मेरी व्यवस्था है।
33) सदन में हमलोगों को गम्भीर विषय की जानकारी मिली । मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या रामलखन सिंह यादव जी यादव महासभा के अध्यक्ष हैं ? इस बात की जानकारी इनको है?

श्री रघुनाथ झा : वे भारत सरकार के कांग्रेस के मंत्रिमंडल के सदस्य हैं।

श्री लालू प्रसाद : ये यादव महासभा के अध्यक्ष हैं या नहीं। यह अलग बात है। लेकिन वे भगोड़े बिकाऊ सांसद के अध्यक्ष जरूर हैं।

श्री चन्द्रदीप सिंह : सभापति महादेय, अभी भी हमारी सरकार जलापूर्ति के मामले में सिरियस नहीं दिखती है। अभी बहुत दिन नहीं हुए हैं, रामलखन सिंह यादव जी इस बेंच पर बैठते थे और कुछ दिनों के बाद वे उस बेंच पर चले गये और फिर इस बेंच पर चले आये। वैसे लोगों की चर्चा कर ये जलापूर्त्ति जैसे सवालों पर विचार न कर समय को बर्बाद कर रहे हैं। अभी भी सरकार इस मुद्दे पर गम्भीर नहीं है। सभापति महोदय, टोका-टोकी में मेरा समय चला गया। 2 मिनट हमें और समय दिया जाय।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : सभापति महोदय ...

सभापति : आप बैठ जाइऐ। बिना परमिशन के आप नहीं बोल सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद : सोनिया गांधी जी का पत्र हमको नहीं मिला है। अगर पत्र मिलेगा, सोनिया जी ऐसे सवालों पर हमें बुलायेंगी तो उनके प्रति हम हमदर्द हैं। हम निश्चित रूप से अपना विचार रखेंगे।

श्री शंकर प्रसाद टेकरीवाल : सभापति महोदय, माननीय सदस्य श्री कुमुद रंजन झा जी ये मुख्यमंत्री जी से कहकर बोलते हैं यह असंसदीय शब्द है। इस तरह से नहीं कहा जाता है इनको सीखना चाहिए।

सभापति : टेकरीबाल जी, आप भी मैथिली इलाके से आते हैं। ये मैथिली में बोल रहे हैं।

श्री चन्द्रदीप सिंह : सभापति महोदय, मैं दो बात कहना चाहता हूं। जो चापाकल 92-93 का ये दे रहे हैं उसको ये सभी जगह दे दें। दूसरा जो घनी आबादी वाले गांव हैं, वहां सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के द्वारा शौचालय बनाने की बात थी, 15 सौ रुपये में तीन यूनिट बनवाना था लेकिन, कहीं भी नहीं बनाया गया है। हम अनुरोध करते हैं कि घनी आबादी वाले गांव में ज्यादा पैसा देकर अधिक-से-अधिक शौचालय

का निर्माण कराया जाय। सभापति महोदय ! पीरों में 8 वर्षों से पानी टंकी अधूरा पडा हुआ है। हम मंत्री जी से आग्रह करते हैं कि उस पानी टंकी को ये चालू करवा दें ताकि नोटिफायड एरिया और आसपास के गांव में पानी उपलब्ध हो । सभापति जी, मंत्री जी इस सब बातों को नोट नहीं कर रहे हैं । चौथा है कि गिरिडीह में लोरिंग नहीं हुआ है। वहां 6 सौ चापाकल का लोरिंग नहीं हुआ है। वहां भी एक एक-एक चापाकल दिया गया है। सरकार की घोषणा हुई थी, खासकर मुख्यमंत्री जी की घोषणा हुई थी कि 5-5 चापाकल देंगे। हम मांग करते हैं कि सरकार इसको पूरा करे ।

श्री लालचंद महतो : सभापति महोदय, मैं पी० एच० ई० डी० की मांग के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। सभापति महोदय, मैंने मंत्री जी के भाषण को अक्षरशः पढ़ने की कोशिश की है। प्रतिवेदन में ये कहे हैं कि सप्तम पंचवर्षीय योजना के अंत तक राज्य सरकार सभी ग्रामों में औसतन 250 की आबादी पर कम-से-कम एक चापकाल, जलश्रोत का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। सभापति महोदय, आप जानते हैं कि बिहार की आबादी लगभग 7 करोड़ है, 9 करोड़ होने जा रही है। 9 करोड़ की आबादी के बीच में 250 की जनसंख्या पर एक-एक जलश्रोत देने का काम कर रहे हैं। अब तक 250 के हिसाब से कितने दिये गये, इसकी जानकारी इसमें नहीं दी गयी है। हम चाहें कि मंत्री जी कृपया जानकारी देने का कष्ट करेंगे । प्रतिवेदन में यह भी कहा गया है कि 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के आधार पर जल उपलब्ध हो इसके लिए 150 व्यक्ति पर जलश्रोत किया जाना चाहिए ।

इस मापदंड के आधार पर करीब 45171 गांव सर्वेक्षण के बाद पाये गये हैं, जहां अभी भी पूर्णरूप से पानी पीने की व्यवस्था नहीं है। विभागीय बुकलेट जो बांटा गया है, उसके पृष्ठ-45 में कहा गया है कि 150 व्यक्तियों पर एक जल श्रोत की आवश्यकता आंकी गई है, जिससे राज्य के 67466 राजस्व ग्रामों का पता लगाया गया है। सरकार जवाब देते समय इस बात पर प्रकाश डालेगी ।

सभापति महोदय ! देश को आजाद हुये 40-45 वर्ष हो गये लेकिन आज तक गांवों में, गरीबों की झोपड़ियों में, आदिवासियों के टोलों में हम

पानी उपलब्ध नहीं करा पाते हैं। आज आप पूरे बिहार में चले जायें, शहर में चले जायें तो हम पायेंगे कि कांग्रेस और केन्द्र सरकार की कृपा से पूरी गलियों में कोको-कोला और पेपसी कोला मिलेगा, लेकिन गांव के गरीब लोगों को पानी नहीं दे सकते हैं, हरिजन आदिवासी को पानी नहीं दे सकते हैं। पूरे देश में कोको-कोला, पेपसी कोला का व्यापार 1800 करोड़ रु० का होने वाला है 94-95 के बीच । इस साल इस देश से 500 करोड़ रुपये अमेरिका ले जाने का काम कर रखा है। इन कांग्रेसियों के द्वारा देश को गिरवी रखने का काम किया गया है। हमारे गांव में पानी नहीं है, हम नल, कुआं, चापाकल नहीं लगा सकते हैं लेकिन पेपसी कोला, कोको-कोला के माध्यम से पूरे देश को गिरवी रखने का काम कर रहे हैं, इससे 500 करोड़ रुपये इस देश का अमेरिका जायेगा। बिहार को जितना पैसा मिलना चाहिये था केन्द्र सरकार के द्वारा, उतना पैसा बिहार को नहीं दिया जा रहा है माननीय मंत्री ने कहा है कि 150 प्रति व्यक्ति एक जलश्रोत देंगे, लेकिन हम 150 पर क्यों, 50 पर दे सकते थे, अगर उतना पैसा हमको केन्द्र सरकार से मिलता । पूरे देश के लोगों को, तमाम लोगों को अह्वान करना चाहता हूं कि जहां-जहां पेपसी-कोला, कोको-कोला बिकता है, उसको छोड़े और कांग्रेसियों को उखाड़ फेंकने का काम करे। सभापति महोदय, मैं धन्यवाद चाहता हूं। इस विभाग में बहुत अच्छा काम हो रहा है, प्रयास बहुत अच्छा हो रहा है। साथ-साथ अनेक कार्यक्रमों का इस बुकलेट में चर्चा की गयी है, उसका मैं समर्थन करता हूं । इसके साथ-साथ मैं अपने क्षेत्र के गिरिडीह जिला के डुमरीप प्रखंड की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। डुमरी प्रखंड में 93 साल में 350 चापाकल गाड़ा गया लेकिन 150 में ही चापाकल में हेड लगा है, इसलिये मै मांग करता हूं कि सभी चापाकल में हेड लगाया जाय। उसी तरह से नवाडीह प्रखंड में 91-92 में विधायक कोटा का जो चापाकल गाड़ना था, उसका आधा भी नहीं गाड़ा गया है। इसलिये मैं मांग करता हूं कि वहां पर पूरा चापाकल गड़वाया जाय। साथ-साथ मैं कहना चाहता हूं कि गिरीडीह जिला में 30 साल पहले जो पानी की व्यवस्था शहर में की गई थी, वही व्यवस्था आज भी है। जबकि जनसंख्या चार गुना अधिक हो गयी है। इसलिए वहां जनसंख्या की क्षमता के मुताबिक पानी की व्यवस्था करायी जाय । डुमरी में जो पानी की व्यवस्था

नल के द्वारा है, वह 82 में बना है, उसको स्टार्ट नहीं किया गया है, जिससे आम जनता को लाभ नहीं मिल रहा है। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि 10 साल से डमरी प्रखंड में जलापूर्ति योजना जो ठप्प पड़ी है, उसको चालू कराने का काम करें। साथ-साथ मैं मधुबनी के बारे में कहना चाहता हूं। मधुबन में 10 हजार की आबादी है, वहां पर 18 तारीख से उग्रवादी के द्वारा जलश्रोत काट दिया गया है, जिससे वहां के लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। वहां पर लोग देश-विदेश से आते हैं, इसलिये उसको जोड़ने का काम सरकार करे ।

सभापति महोदय, इसी तरह से नगर निगम की सफाई ठप्प हैं, नगर निगम की हड़ताल चल रही है। मैं मुख्यमंत्री से कहूंगा कि जो हड़ताल चल रही है, उसको निगोसियेशन करके हड़ताल समाप्त कराया जाय और सफाई की व्यवस्था करायी जाय। सभापति महोदय, मेरा कहना है कि डुमरी, बेरमो, फुसरो को नोटिफायड एरिया घोषित कर दिया गया है लेकिन 10 साल से एक पैसा नहीं दिया जा रहा है। इसलिये वहां की फंड की व्यवेस्था करायी जाय, नहीं तो पंचायत ही बना दिया जाय ताकि जवाहर रोजगार योजना से वहां विकास का काम हो सके। इतना ही कहकर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री टीकाराम मांझी : सभापति महोदय । मैं जलापूर्ति, सफाई और शहरी विकास की मांग के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं। चन्द बातों की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। सभापति महोदय, यह सही बात है कि आजादी के 47 वर्षों के बाद भी गांव के रहने वाले और शहर के रहने वाले लोगों की आधी आबादी को पेयजल की आपूर्ति नहीं करा पा रहे हैं । यह सचमुच में सरकार के लिये और हमलोगों के लिए शर्मनाक बात है। वैसे तो मैंने देखा है कि विशेषकर पठारी क्षेत्रों में जलापूर्त्ति के लिये ट्यूबबेल की भयानक समस्या है ऐसे तो लिखा गया है कि 150 लोगों पर 1 चापाकल का लक्ष्य है लेकिन हमलोगों को पिछले साल का जो अनुभव बताता है कि 92-93 में विधायक की अनुशंसा पर जो चापाकल गाड़ना था, घाटशिला और दालभूम प्रखंड में, उसमें आधी से भी कम गाड़ा गया है, 93-94 में तो जीरो है। ऐसी स्थिति में हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि 150 लोगों

पर चापाकल की व्यवस्था करेंगे । आदिवासी सब प्लान के तहत इसको कैसे पूरा किया जा सकता है। सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा है कि हमारे पठारी क्षेत्रों में सचमुच में 50 प्रतिशत से अधिक चापाकल खराब हैं और हमलोग जब-जब 20 सूत्री की बैठक में या अन्य बैठक में इस मुद्दा को उठाते हैं तो इनके पदाधिकारी कहते हैं कि नल को बदलने के लिये, पाईप बदलने के लिए पैसा नहीं है, हेड नहीं है, इस ढंग से सब चापाकल बेकार पड़े हुये हैं। जिस गांव के लोग आर्थिक रूप से मजबूत हैं, वे लोग चन्दा करके चापाकल को ठीक करा लेते हैं । हमारे यहां घाटशिला सब-डिविजिनल हेड क्वार्टर है, यहां पर भी आधे से कम आबादी को पेयजल की आपूर्ति हो रही है, इसलिये यहां पर जलापूर्ति की व्यवस्था करायी जाय। बालूडीह, नरसिंगार में 10 साल पहले ट्यूबवेल गाड़ा गया है लेकिन पाईप नहीं लगाने के कारण जलापूर्ति नहीं हो पा रही है। इसलिये वहां पर पाईप लगाकर जलापूर्ति की व्यवस्था करायी जाय । मानगो जमशेदपुर का अभिन्न अंग है। यहां पर 3 लाख की आबादी है यहां पर भी आधे से कम लोगों को ही जलापूर्ति की व्यवस्था करा पा रहे हैं, इसलिये मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वहां पर सभी लोगों को जलापूर्ति की व्यवस्था करायी जाय। इतना ही कहकर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री युगेश्वर झा : सभापति महोदय, मुझे दो मिनट का आदेश हुआ है। मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूं, खासकर के माननीय मुख्यमंत्री से कि ए० आर० पी० को पैसा 93-94 का पैसा केन्द्र सरकार के द्वारा विमुक्त हो चुका है। अभी तक किसी जिले में ए० आर० पी० का फण्ड नहीं गया है हमको जानकारी मिली है कि ए० आर० पी० का फण्ड जिससे चापाकल गाड़ना था वह कर्मचारियों के दरमाहा पर बांटा गया है, इसका मंत्री जी जवाब देंगे । दूसरी बात सभापति महोदय आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि 80-81 के समय में आप भी सदस्य थे । 90 चापाकल एक साथ लिया गया था। 81-82 में 5 चापाकल लिया गया था वह भी गड़ गया। अभी क्या बात हो गयी है ? 2 चापाकल की घोषणा की 90-91 में, इसमें क्या हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री इसमें विभाग फ्रीडिज्म कर रहा है माननीय मुख्यमंत्री

के द्वारा विधायक और सदन को धोखा दिया जा रहा है। माननीय विधायक का अलग से फण्ड है। ए० आर० पी० का चापाकल और एम० एन० पी० का चापाकल को विधायक कोटा मान लेना यह घोर अन्याय है सरकार फ्रीडिज्म करती है, विधायकों के साथ भी धोखा करती हैं।

श्री दिलीप कुमार राय : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि और खासकर इस बिन्दु की तरफ कि बिहार पठारी विकास परियोजना के तहत विश्व बैंक की सहायता से यह पठारी इलाके में, इसके तहत 67 प्रखण्डों में 150 व्यक्ति पर एक जल श्रोत की व्यवस्था करनी है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत डिल्ड नलकूप इंडिया मार्क 3,6000 पम्प की व्यवस्था की गयी है। पहले साल, जिस पर न्यूनतम लागत बिहार पठारी विकास परियोजना जो इसको गड़वाने जा रही है, जिसपर अनुमानित लागत 32 हजार रुपये के करीब आ रहा है। सरकार इस पर 32 हजार रुपये खर्च करने जा रही है जबकि यह नलकूल अगर पी० एच० ई० डी० के द्वारा गाड़ा जाय तो इसपर 20 हजार रुपये खर्च आता है। हमको ऐसी जानकारी मिली है। इस बारे में माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे। यह 12 हजार रुपये नलकूप का जो बंदरबांट हो रहा है इसमें करोड़ों रुपये लगा हुआ है और घपला किया जा रहा है। मंत्री जीं निश्चित रूप से इसका जवाब देंगे । मंत्रीजी हमारे क्षेत्र में गये हुये थे और महाम्दा में जो एक पानी ठंकी का उद्घाटन किया था वहां यह आश्वासन दिया था कि हरिजन और पिछड़ी जाति के एरिया में पानी का लाइन बिछा दिया जायेगा, मगर आज तक नहीं किया गया। जिस पावर का पम्प और जो मोटर लगाना था वह नहीं लगाया गया। कृपा करके लगाने की व्यवस्था करेंगे । साथ ही 90-91, 91-92 और 92-93 का पूरा चापाकल नहीं गाड़ा गया। आपसे आग्रह है कि इसको गड़वाने की व्यवस्था करेंगे । मैं इन्हीं शब्दों के साथ कटौती प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : सभापति महोदय, हमारे औरंगाबाद जिले के सारे चापाकल और सिमेन्ट का प्लेटफार्म कार्यपालक अभियंता, एस० डी० ओ० और कनीय अभियंता बेचकर खा रहे हैं। माननीय सदस्य ब्रजमोहन बाबू ने भी लिखकर दिया है और हाउस में निवेदन भी किया है। हम मंत्री जी से जानना चाहते हैं । सारे औरंगाबाद जहां ।1

प्रखंड हैं, इसकी जांच करवा दीजिये ताकि मार्च में जो पैसे की लूट हुई है, इसकी जानकारी हो सके और दोषी को सजा हो सके।

सभापति :माननीय सदस्य को यह जानकारी होनी चाहिये। पी० एच० ई० डी० में एक राज्य मंत्री भी है। उनको इन्ट्रोडयूस किया जा रहा है। हमारे लिये भी एक इनफारमेशन है राज्य मंत्री जो हैं, मैं आपको बताता हूं, वह हैं श्री शिव चरण मेहता ।

श्री शिव चरण मेहता : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से बजट के समर्थन में और कटौती प्रस्ताव के खिलाफ में हस्तक्षेप करने के लिए खड़ा हुआ हूं। सभापति महोदय, मैंने सारे माननीय सदस्यों को बड़े गौर से सुना, जो भी वक्तव्य था सुना लेकिन, मैंने सोचा था कि यह लोग कुछ अच्छा सुझाव देंगे । मैं यह कहना चाहता हूं कि पानी ही जीवन है, जल ही जीवन है। इसलिये मैं यह समझता था कि यह लोग कुछ अच्छा सुझाव देंगे और माननीय मंत्री के द्वारा जो भी काम किया गया है खासकर के सुखाड़ के समय में देख सकें कि जब यह सुखाड़ हुआ था तो किस तरह माननीय मुख्यमंत्री पी० एच० इ० डी० के पदाधिकारी को निर्देश देते थे कि सुखाड़ का समय है, जहां भी पानी की कमी है वहां अविलंब पानी की व्यवस्था करें। हमारे यहां पी० एच० इ० डी० का जो भी चापाकल खराब या इसकी मरम्मति की गयी । सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि चापाकल जो गाड़ा गया है वह चौराहों पर, स्कूलों में, मदरसों में, गरीब की झोपड़ी में गाड़ा गया है वह चौराहों पर, स्कूलों में, मदरसों में गरीब की झोपड़ी में गाड़ा गया है।

सभापति महोदय, मैं कुछ उपलब्धि कहना चाहूंगा कि इस सरकार के द्वारा जो काम हुआ है, इसके बारे में बताना चाहता हूं कि 93-94 में टाटा का पाइप माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा दिया गया था और माननीय मुख्यमंत्री जहां भी जाते थे और एलान करते थे और पी० एच० इ० डी० के जो पदाधिकारी थे उनको बोलते थे कि बोलो टाटा का पाइप खरीदे हैं और सब जगह टाटा का पाइप लगायेंगे । इस पर लिखा गया बिहार सरकार। इस तरह से 40 वर्षों में जो लूट खसोट हुआ था कांग्रेसी शासन में, वह माननीय लालू यादव के शासन में दूर हो गया ।

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।)

यह लोग जो कहते हैं कि पैसा फिक्सड डिपोजिट में जमा किया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि पूर्णिया में सहरसा में, मधेपुरा में शुद्ध जल की व्यवस्था की गयी है वहां पर शुद्ध पेय जल की व्यवस्था के लिए इंतजाम किया गया है।

अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस राज में जो भी चापाकल लगाया गया था वह बड़े-बड़े लोगों के घरों में लगाया गया था ।

लेकिन आप इसका सर्वेक्षण करके देखें कि हमने जो चापाकल लगाये हैं, वह गरीबों के घर में लगाये हैं, गरीबों के झोपड़ी के किनारे लगााये हैं, मदरसा में लगाये हैं, स्कूल में लगाये हैं और इस तरह से हमने इन लोगों के उत्थान के लिए कार्म किया है।

अध्यक्ष : अब सरकार का उत्तर होगा, माननीय मंत्री ।

सरकार का उत्तर

श्री गजेन्द्र प्रसाद हिमांशु : अध्यक्ष महोदय, जिन माननीय सदस्यों ने इस वाद-विवाद में भाग लिया है, मैं उनके प्रति अभार प्रकट करता हूं । जल की जो समस्या है, जिनके बारे में यहां चर्चा की गयी है, जल की जो समस्या है, यह अपने राज्य की ही समस्या नहीं है, बल्कि यह पूरे राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय समस्या है। आप जानते होंगे कि बिहार ही एक ऐसा स्टेट है जहां 250 प्रति व्यक्ति पर एक सोर्स पानी का देने का काम किया गया है। हरियाणा भी इसके पीछे है। बिहार के जो लोग हैं वे खुशनसीब हैं कि यहां मीठा पानी इनको प्राप्त है, अधिकांश जगहों में मीठा जल नहीं मिलता है। देश के अन्य प्रान्त जैसे आपके राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटक, तमिलनाडु, इन राज्यों में जाते हैं तो देखते हैं कि वहां खारे जल की समस्या है । उनलोगों को मीठा जल नहीं मिल पाता है।
37) वहां हम देखते हैं कि नर्मदा नदी के जल का विवाद है, कावेरी नदी के जल का विवाद है, सतलज और झेलम का विवाद का मामला चल रहा है, इन जगहों में पीने के पानी की समस्या है। हम सभी जानते हैं कि कावेरी नदी के जल का विवाद तमिलनाडु में है लेकिन, खुशनसीब हैं बिहार के लोग कि यहां पानी के श्रोत कुछ ज्यादा हैं। इसके बावजूद भी

हमलोगों के यहां शुद्ध जल जो हैं, वह तीन प्रतिशत ही हैं और हमें मीठा जल मिल पाता है, जबकि सारे देश में, दुनिया में तीन भाग में पानी है लेकिन मीठा जल तीन प्रतिशत में ही पाया जाता है। यह जो जल की समस्या है यह मामूली समस्या नहीं है, पूरे राष्ट्र का और अंतर्राष्ट्रीय समस्या है । लेकिन बिहार इस मामले में, पानी के मामले में आगे है।

पंचम पंचवर्षीय योजना में हमारे यहां इस दिशा में काम शुरू हुआ और ग्रामीण जलापूर्ति के लिए सबसे पहले कार्यक्रम बना था, गांव की पहचान के लिए कहां–कहां टोले हैं, कहां–कहां पानी नहीं पाये जाते हैं और संयुक्त राष्ट्रसंघ ने भी 1980 और 90 के दशक को अंतर्राष्ट्रीय जलापूर्ति एवं स्वच्छता दशक के रूप में मनाया गया। इन वर्षों में कुछ स्टैंर्ड, कुछ मानक तय किये गये जलापूर्ति के लिये कि कितने लोगों पर जल मुहैया होनी चाहिए । भारत सरकार ने भी उसी मार्गदर्शन का अनुसरण किया और भरत सरकार ने भी 250 प्रति व्यक्ति पर पानी देने का निश्चिय किया है। तो हमारे बिहार राज्य में सातवीं पंचवर्षीय योजना में ही 250 प्रति व्यक्ति पर पानी का श्रोत मिल चुका है और अब 210 गांव ऐसे बचे हैं, जहां इस साल उनको भी यह श्रोत पहुंचा देंगे । अब हमलोग आठवीं पंचवर्षीय योजना में प्रवेश किये हैं । दो साल बीत गया, 150 व्यक्ति पर एक चापाकल हम देंगे, जिससे 40 लीटर पानी उनको मिल सके और इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। माननीय सदस्यों ने जो चर्चा पठारी इलाके के बारे में की है, उसमें जनजाति लागों के बारे में, अनुसूचित जाति के बारे में कि चापाकल नहीं गाड़े हैं, चापाकल नहीं है, पानी के लिए हाहाकार है। अध्यक्ष महोदय, कुछ माननीय सदस्यों ने यह बतलाया कि कहीं 300 गाड़े गये तो उसमें पम्प 150 में ही लगाये गये । हमने यह भी स्वीकार किया है कि हमारे यहां और अधिक पानी की जरूरत है। मै स्वयं स्वीकार करता हूं कि पानी अति आवश्यक चीज है, हर घरों को जरूरत है, मगर पानी की दिशा में जितना काम किया है, वह कम नहीं है। जहां तक विधायकों के चापाकल की बात है, उसके बारे में बाद में कहना चाहूंगा। इसलिए हमने कहा कि अध्यक्ष महोदय को अभी जो बतलाया गया है कि जनजाति क्षेत्र में, पठारी इलाका में चापाकल

नहीं है लेकिन, 151 हजार 111 नलकूप लगाये गये हैं दक्षिण बिहार के पठारी इलाकों में, वहां आपने देखा कि इधर सुखाड़ का समय बीत गया, इन दो सालों में सुखाड़ का मुकाबला कैसे किया ।

जहां पानी का लेयर नीचे चला गया–पठारी इलाके में, विश्व बैंक की मदद से पठारी विकास योजनायें चलायी जा रही हैं, जिसमें तय किया गया है कि तीन वर्ष में तेरह हजार चापकल, नलकूप लगाये जायेंगे और अभी इस साल दो हजार चापाकल लग चुका है इस योजना में और वर्ष 96 तक कुछ पठारी इलाके जहां जनजाति लोग बहुत हैं, उन सारे इलाकें है।, ऐसे 67 ब्लॉक हैं आदिवासियों भाइयों का, उसमें हमारा लक्ष्य 6 हजार 60 हैं, जिसमें हम दो हजार पूरा कर चुके हैं, इस तरह से चापाकल लगाने का काम हम कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि चापकल नहीं लग रहा है। आप जानते हैं कि चापाकल की दिशा में कितना हमलोगों ने काम किया है । पहले इंडिया मार्क–11 लगता था दक्षिण बिहार के लिए, पठारी क्षेत्रों के लिए, आप जानते होंगे इण्डिया मार्क–11 कुछ लगता है लेकिन, नई टेकनोलोजी इजाद हुई है और अब इण्डिया मार्क–111 लगाये जा रहे हैं जिससे पानी निकालने में मदद हो रही है, आसानी हो रही है और मैं बतलाना चाहता हूं कि चापाकल के लिए पांच जो लोग हैं, उनको ट्रेनिंग देंगे, पार्ट–पूर्जा देंगे ताकि वे चापाकल ठीक कर सकें। दक्षिण बिहार के जो ड्रील नलकूप हैं वे खराब भी कम होते हैं, वहीं उत्तर बिहार के चापाकल ज्यादा खराब होते हैं और खराब चापाकल की संख्या मात्र 13 प्रतिशत ही है, जबकि मानक के अनुसार 15 प्रतिशत तक हमलोगों को माफ है । लेकिन 13 प्रतिशत उत्तर बिहार के चापाकल खराब है। और दक्षिण बिहार के जो ड्रील नलकुप हैं वे मात्र पांच प्रतिशत ही खराब हैं। इसलिए ऐसी बात नहीं है कि सभी चापाकल खराब है। सरकार ने इधर जो काम किया है, आप जानते होंगे कि दक्षिण बिहार में,
38) चक्रधरपुर में जो हमने काम किया है, वहां की पाईप जलापूर्ति योजना वर्षों से बन्द पड़े थे, उसको हमने चालू कराया है, उसी तरह से जमशेदपुर अवस्थित मानगो इलाका में लोगों को पानी नहीं मिलता था, हमने उसको चालू कर दिया है। टावर और टंकी बनाकर। भुआ प्लांट जो वर्षों से खराब था, उसको हमने चालू किया है, खरकई नदी से डैम में पानी देने

का काम लिया है, जिससे जमशेदपुर के पूरे शहर में पानी की तकलीफ नहीं रहेगा। इस तरह से हमने पाईप जलापूर्ति योजनाओं को चालू करने का काम किया है। सिवान जिला के अन्दर ब्लॉक में नई पाईप जलापूर्ति योजना का उद्घाटन किया है साथ ही हमलोगों ने हसनपुर में काम किया है। हमारे माननीय सदस्य श्री राय जी बोल रहे थे कि समस्तीपुर के इलाके के बारे में बतलाया कि जो उद्घाटन हुआ है, इनका कहना है कि और पाईप बढ़ना चाहिए था। पटना के दीघा वाटर पम्प को चालू किया गया और उसके बाद मुंगेर के तारापुर, असरगंज में चालू किया गया। सभी जगह की कई पाईप जलापूर्ति योजना जो वर्षों से बन्द थी उनको चालू किया गया। इसलिए हम पेय जल की दृष्टिकोण से पीछे नहीं हैं, पेय जल की दिशा में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं...

श्री संजीव प्रसाद टोनी : अध्यक्ष महोदय, 55 चापाकल चोरी हो गये, इस संबंध में सरकार स्पष्ट करे ...

श्री गजेन्द्र प्रसाद हिमांशु: महोदय, थाना में मामला दर्ज कराइए, हमलोग कार्रवाई करेंगे। जहां चोरी हुई है वहां के थाना में एफ० आई० आर० कीजिए।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने एक बात का जिक्र किया है कि अपने यहां स्वच्छ जल की समस्या है, बिहार के उत्तर बिहार के 12-13 जिले ऐसे हैं। जहां लौह-युक्त पानी पाये जाते हैं।

किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, मधेपुरा, कटिहार, बेगुसराय और समस्तीपुर के इलाके में लोहयुक्त पानी पाया जाता है। यह समस्यां है और इस समस्या की ओर हमलोगों का ध्यान है। अभी तक हमलोगों ने पिछले साल 49 लौह निष्कासन यंत्र लगाया है और इस साल हमलोग 3 सौ लौह निष्कासन यंत्र लगाने जा रहे हैं। इस तरह से हमारा प्रयास है कि हम उनलोगों को आयरन मुक्त पानी दिलायें क्योंकि आयरन से नुकसान होता है। अपने राज्य में एक दो ब्लॉक पलामू में हैं जहां दोषयुक्त पानी है। उन दो ब्लौक में फ्लूराईड नामक केमिकल पाया जाता है, जबकि हमलोगों के यहां आयरन युक्त पानी पाया जाता है आयरन युक्त

पानी को दोष मुक्त करने जा रहे हैं हमने अपने राज्य में घेघा को खत्म कर दिया। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि घेघा खत्म हो गया है यह बात जरूर है कि पहले चापाकल नहीं था, ड्रील्ड ट्यूबवेल नहीं था तो लोग कुआं का पानी पीते थे। कुआं का पानी स्वास्थ्य के लिए अहितकर होता था और उससे हैजा और घेघा नामक बीमारी होती थी। अब लोग कुएं का पानी नहीं पीते हैं। माननीय सदस्य टेकलाल महतो जी ने कहा कि कुआं बनवा दीजिये। इनको मैं कुआं बनाने की सलाह इसलिए नहीं दूंगा और कुआं इसलिए नहीं बनाऊंगा, क्योंकि कुआं बनाने से फिर वह घेघा नामक बीमारी उभर जायेगी, पुरानी बीमारी जो दब गयी है। कुएं का पानी शुद्ध नहीं माना जाता है । वह दूषित पेयजल माना जाता है। इसलिए कि उसमें खर पतार गिरता है। कुएं का पानी दोषमुक्त नहीं होता है। अध्यक्ष महोदय, गहरा जहां लेयर चला गया है उसके लिए हमने 450...

श्री युगेश्वर झा : विधायक कोटा के बारे में न बतलाईये कि चापाकल ...

श्री गजेन्द्र प्रसाद हिमांशु : मैं बतलाऊंगा । आप क्यों नहीं सुनना चाहते हैं। आप कहें कि कुछ नहीं हुआ और जब बतलाना शुरू किया तो विधायक कोटा के बारे में कहिये । अध्यक्ष महोदय, यूनिसेफ की सहायता से हमको 450 तारा चापाकल मिला है। तारा चापाकल उन खास जगहों के लिए हैं, जहां का पानी का लेयर काफी नीचे चला गया है। पठारी जिले में, सुखाड़ प्रभावित जिले में 8-10 जिले में, तारा पम्प को अधिष्ठापित करेंगे और उसी तरह से ...

श्री हिन्द केशरी यादव : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मंत्री जी ने बतलाया कि हसनपुर या अन्य जगह लगी है पानी टंकी और उसका सब लोग उद्‌घाटन और शिलान्यास बस कुछ करते हैं,
39) लेकिन छः वर्ष पूर्व से जो हमारे मीनापुर में नरम, कथैन, गंज, सिवायपट्टी, टेंगराही, टेंगरहा और बनगहरा इन तमाम जगहों में पानी टंकी स्कीम जलापूर्ति योजना के तहत स्वीकृत है, लेकिन इन तमाम स्कीमों को स्थगित कर दिया गया है और अपने-अपने घर में लोग पानी टंकी का उद्‌घाटन कर रहे हैं। इसपर मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। इसपर अध्यक्ष

महोदय, आप समूचे सदन के गार्जियन हैं, आप संरक्षक हैं, आपसे मैं सुरक्षा चाहता हूं कि आखिर में मीनापुर के साथ इस तरह का अन्याय क्यों हो रहा है, जबकि मैं बार-बार इसके लिए अनशन पर बैठा हूं, सत्याग्रह किया हूं इसलिए मीनापुर के बारे में आपका संरक्षण कब मिलेगा ?

श्री गजेन्द्र प्रसाद हिमांशु : इनकी पानी टंकी पर कार्रवाई की जायेगी, पानी टंकी बनाने की कार्रवाई शुरू की जायेगी । अध्यक्ष महोदय, सरकार ने अभी 10 रींग मशीनें खरीदी है। यह इतनी शक्तिशाली है कि वह एक हजार फीट नीचे और 6 सौ फीट नीचे तक ड्रील करेगी । ऐसे आई० टी० एच० 20 एक रींग खरीदा है तथा आई० टी० एच० 10 की 9 मशीनें हमने खरीदी हैं और इससे दक्षिण बिहार के वैसे इलाके में हमें काम करने में मदद मिलेगी, जहां काफी गहराई में पानी का लेयर चला गया है । अध्यक्ष महोदय, ओ० आई० सी० एफ० जो जापान सरकार की...

श्री लालू प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, केशरी जी के निगोसियेशन में, पंचायती में हम थे । उस समय जो उन्होंने किया था तो सत्र समाप्ति के बाद हम चलेंगे वहां और जिन-जिन गांवों का उल्लेख आप कर रहे हैं सब जगह पानी की व्यवस्था और जल श्रोत या टंकी की बात सब काम हो जायेगा ।

श्री गजेन्द्र प्रसाद हिमांशु : जापानीज सरकार की मदद से बौद्ध तीर्थों के उन्नयन का काम कर रहे हैं जो अपने आप में एक उल्लेखनीय कार्य है। बोध गया में जापान सरकार की मदद से हम काम करा रहे हैं । मदद के रूप में 11 करोड़ 20 लाख हमें मिला था और इससे हम बोधगया और राजगीर में काम करा रहे हैं और इससे दो पानी की टंकी बन रही है। फिर हम वैशाली में काम करवा रहे हैं इस तरह से जो हमारा काम चल रहा है अध्यक्ष महोदय, आप देखेंगे कि माननीय सदस्यों ने कहा कि कोई काम नहीं हुआ । मैं बताना चाहता हूं कि 1993-94 में जो काम हुए हैं उसमें 3680 चापाकल गड़े हैं और 22 हजार जो बंद चापाकल थे उसकी विशेष मरम्मती की गयी है। अध्यक्ष महोदय, जो

विधायकों की अनुशंसा पर चापाकल गाड़ना था 93-94 में तो 13 हजार चापाकल गड़वाये गए हैं इसलिए ऐसी बात नहीं है कि काम जो है वह नहीं किया गया है। 1994-95 में हम 7 हजार ग्रामों में टोलेवार स्थापित करने जा रहे हैं। और 3 सौ लौह निष्कासन यंत्र लगाने जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, जो नये श्रोत हम लगाने जा रहे हैं वह है न्यूनतम कार्यक्रम के द्वारा और त्वरित जलापूर्ति के लिए और जो हमारी टेक्नोलॉजी मीशन है उसमें 73584 चापाकल हम नया लगाने जा रहे हैं। इसलिए सरकार जो इस दिशा में काम कर रही है वह निश्चित रूप से सराहनीय कहा जायेगा। अध्यक्ष महोदय, स्वच्छता कार्यक्रम के लिए 1 करोड़ 45 लाख रुपये इस पर खर्च कर रहे हैं और 84 हजार निजी शौचालय का निर्माण होने जा रहा है और 3 सौ सामूहिक शौचालय का निर्माण होगा।

(व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह घोषणा की थी। हम आज भी उस घोषणा पर कायम हैं। महोदय पठारी क्षेत्र में दो चापाकल और समतल क्षेत्र में 5 चापाकल और दोनों मिलाकर बात तय हुयी थी। महोदय, विधायकों की अनुशंसा पर पिछले वर्ष समतल क्षेत्र में 5 और पठारी क्षेत्र में दो तो इसमें 40925 चापाकल और 5166 ड्रिल्ड ट्युबवेल लगना चाहिए था।

महोदय, समतल क्षेत्रों में 5 और पठारी क्षेत्र में दो। इस तरह से 40 हजार 925 चापाकल एवं 5 हजार 166 ड्रिल्ड ट्युबवेल लगाना चाहिये था, कुल राशि 28.22 करोड़ आवश्यक है। इसमें पिछले वर्ष वित्तीय वर्ष में मार्च, 94 में करीब 8 करोड़ रु० रिलीज हुआ जिससे 13 हजार चापाकल लगे। महोदय लक्ष्य नहीं पूरा हुआ। इस वर्ष जो शेष मा० सदस्यों की अनुशंसा से जो हमारी घोषणा है राशि हमलोग उपलब्ध करा
40) रहे हैं।

अध्यक्ष : सब मिलाकर पांच है ?

श्री लालू प्रसाद : महोदय, पांच समतल के लिये और दो पठारी के लिये यही घोषणा थी। इस काम के लिये अभी हमलोगों को पाईप

का आर्डर देना है, यह सारी कार्रवाई चल रही है और निश्चित रूप से जो विभाग का एचीवमेंट है वह बेमिशाल है। महोदय, पहले के जमाने में लूट–खसोट, स्केण्डल होता था, पाइप बेचने का काम होता था । लेकिन हमलोग इसका कार्यरूप दे रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री गजेन्द्र प्रसाद हिमांशु : महोदय, अब मैं माननीय सदस्या श्रीमती वीणा से आग्रह करता हूं कि वे अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें ।

अध्यक्ष :क्या माननीय सदस्या श्रीमती वीणा शाही अपना कटौती प्रस्ताव वापस लेना चाहती हैं ?

श्रीमती वीणा शाही :अध्यक्ष महोदय, मैं कटौती प्रस्ताव वापस नहीं लेना चाहती हूं ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

"इस शीर्षक की मांग 10 रु० से घटायी जाय।"

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : अब मैं मूल प्रस्ताव को लेता हूं ।

प्रश्न यह है कि :

"जलापूर्ति और सफाई" के संबंध में 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान में जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिये 2,42,14,43,000 (दो अरब बेयालीस करोड़ चौदह लाख तैंतालिस हजार) रु० से अनधिक राशि प्रदान की जाय।)

डा० शकील अहमद : महोदय, खड़ा कराकर गिनती करा ली जाय । घंटी बजवाई जाय ।

श्री प्रभुनाथ झा : महोदय, गिनती करा ली जाय।

(व्यवधान)

अध्यक्ष :आपलोगों के कहने के बावजूद हम घंटी नहीं भी बजवा सकते हैं।

श्री शकील अहमद : महोदय, यह जरूरी है।

अध्यक्ष : जरूरी नहीं है।

श्री रघुनाथ झा : अध्यक्ष महोदय, दोनों पक्ष को खड़ा कराकर गिनती करवा ली जाय ।

श्री शकील अहमद : घंटी बजेगी ।

अध्यक्ष : आप लोग जीत गये । घंटी बजायी जाय ।

(घंटी)

अध्यक्ष : अब मैं मूल प्रस्ताव को लेता हूं ।

प्रश्न यह है कि :

"जलापूर्ति और सफाई" के संबंध में 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान में जो व्यय होगा, उसकी पूर्त्ति के लिये 2,42,14,43,00 (दो अरब बेयालीस करोड़, चौदह लाख तैंतालीस हजार) रु० से अनधिक राशि प्रदन की जाय।

यह प्रस्ताव ...

श्री प्रभुनाथ सिंह : विपक्ष में बहुमत है।

श्री रघुनाथ झा : अध्यक्ष महोदय, हां और ना के पक्ष में माननीय सदस्यों को खड़ा कराकर गिनती करा ली जाय।

अध्यक्ष : ठीक है खड़े होकर मतदान करें ।

अध्यक्ष : खड़े होकर मतदान का फल इस प्रकार है :

प्रस्ताव के पक्ष में–139

प्रस्ताव के विपक्ष में–32

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

मांग स्वीकृत हुई ।

11) **अत्यावश्यक लोक महत्व के विषय पर ध्यानाकर्षण सूचनाएं एवं उनपर सरकारी वक्तव्य**

(क) अपराधियों की गिरफ्तारी एवं मृतक के आश्रित को मुआवजा ।